Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-11 01-15 जून, 2023 (पाक्षिक) ₹20

'भाजपा की उपस्थिति देश के सभी जगहों और सारे समाज में है'

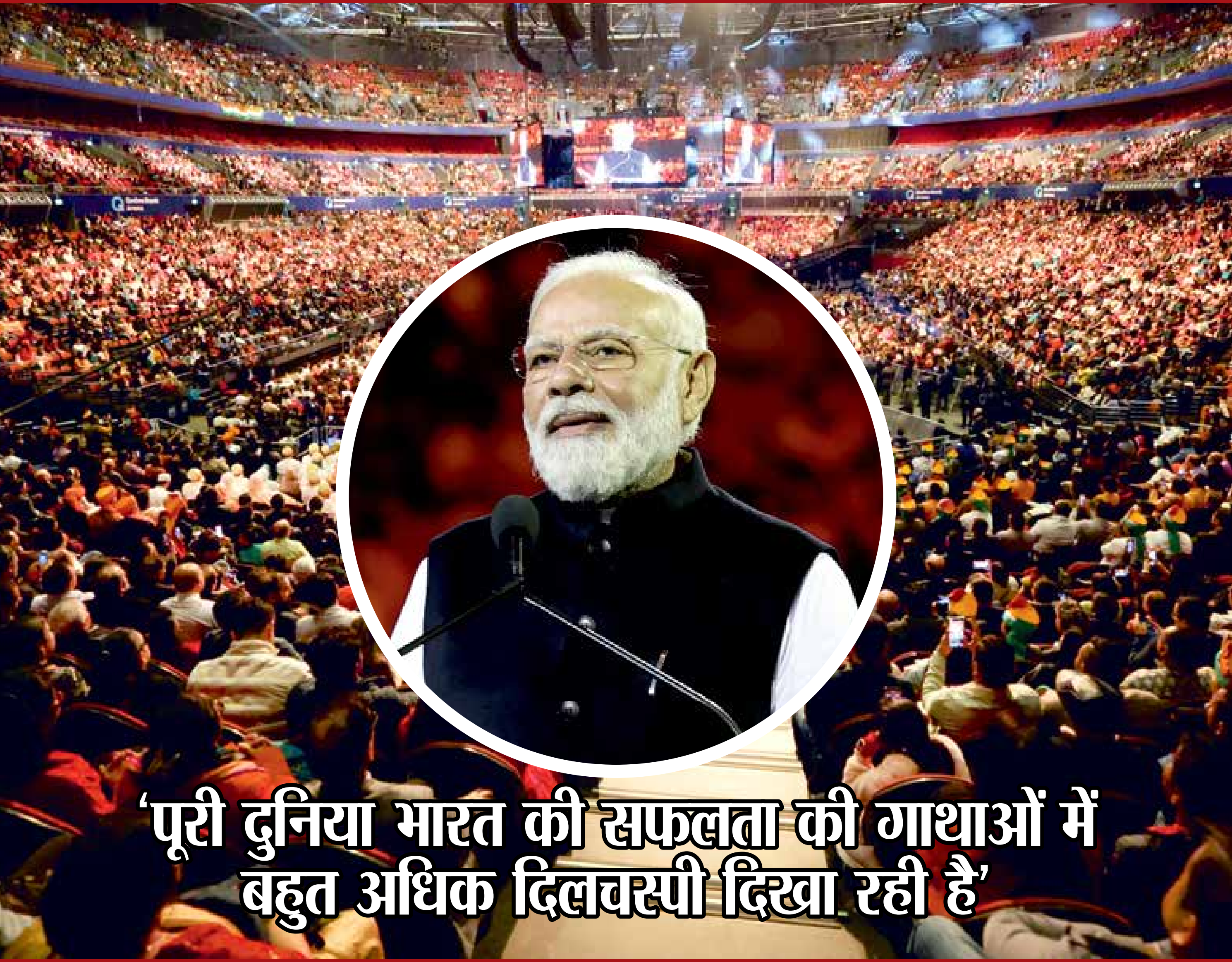

'पूरी दुनिया भारत की सफलता की गाथाओं में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखा रही है'

भाजपा महिला मोर्चा : 'कमल मित्र' का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश में 'प्रजा पोरु यात्रा' का आयोजन

पुणे में 18 मई, 2023 को मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं महाराष्ट्र के अन्य वरिष्ठ नेतागण

विले पार्ले वेस्ट (मुंबई) में 17 मई, 2023 को मुंबई मोर्चा अघाड़ी की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 19 मई, 2023 को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आरंभ किए गए 'कमल मित्र' कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 12 मई, 2023 को 'डेमोक्रेसी इन कोमा – साइलेंस्ड वॉयस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल' पुस्तक का विमोचन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

अहमदाबाद में 21 मई, 2023 को आवास और कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेतागण

संभाजीनगर में 14 मई 2023 को 'वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप महासम्मेलन' में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 'भारत, यूक्रेन संकट के समाधान हेतु बातचीत और कूटनीति का स्पष्ट समर्थन करता है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर 20 मई को हिरोशिमा शहर में जापानी अध्यक्षता के तहत जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के इतर श्री मोदी ने अनेक वैश्विक नेताओं के...

14 'भाजपा की उपस्थिति देश के सभी जगहों और सारे समाज में है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने महाराष्ट्र के दो दिवसीय...

17 अब महिलायें बराबरी नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 मई, 2023 को...

18 भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी 17 मेयर सीटों पर शानदार जीत हासिल की

भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की और मेयर पदों की सभी 17 सीटों और कुल...

29 गुजरात की 'डबल इंजन' सरकार दोगुनी गति से काम कर रही है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को गुजरात के गांधीनगर में लगभग 4400...

वैचारिकी
अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा / **अटल बिहारी वाजपेयी** 26

श्रद्धांजलि
अंबाला लोकसभा सदस्य रतन लाल कटारिया नहीं रहे 28

रिपोर्ट
भाजपा ने आंध्र प्रदेश में 'प्रजा पोरु यात्रा' का आयोजन किया / **सुनील देवधर** 30

अन्य
हम आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे: प्रधानमंत्री 19

कैबिनेट ने उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को दी मंजूरी 20

शून्य से नीचे पहुंची थोक महंगाई दर, खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी आई कमी 21

प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित 23

'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में उपलब्ध नल से जल 24

मोदी स्टोरी 25

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II के अंतर्गत 50 प्रतिशत गांव अब खुले में शौच मुक्त 31

प्रधानमंत्री ने ओडिशा में अनेक रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

बीते नौ वर्षों से भारत अपनी प्रगति के लिए सभी राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कठिन से कठिन वैश्विक हालात में भी देश में विकास की गति कायम है।

(18 मई, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में कौशल विकास की महत्ता को ध्यान में रखकर कई नीतियां बनाई गई हैं। जिसका सफल क्रियान्वयन महाराष्ट्र की डबल-इंजन सरकार में हुआ है। इससे प्रदेश के लाखों युवा लाभान्वित होकर सेवा व स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हुए हैं।

(18 मई, 2023)

अमित शाह

आज द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। मोदी सरकार एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर तटीय सुरक्षा को अभेद्य बना रही है। इसी दिशा में NACP अर्धसैनिक बलों व तटीय राज्यों की सुरक्षा बलों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर समुद्री ताकत बढ़ाएगा।

(20 मई, 2023)

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। रक्षा मंत्रालय उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनका समाधान करने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

(19 मई, 2023)

बी.एल. संतोष

6 दिन! 3 देश — जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया! 3 शिखर सम्मेलन – जी 7, क्वाड और पैसिफिक बैठक। 12 वैश्विक नेताओं से मुलाकात। 50 अनुबंध, उद्योग और निवेशकों के साथ बैठकें। दो शीर्ष पुरस्कार और अब सुबह 11 बजे दिल्ली-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी!

(25 मई, 2023)

डॉ. एस. जयशंकर

हिंद महासागर के राष्ट्रों पर आज अपने मूल्यों, प्रथाओं और यथार्थता को लेकर एक आख्यान को आकार देने की जिम्मेदारी है। यह जरूरी है कि उनकी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को दुनिया के सामने पेश किया जाए।

(12 मई, 2023)

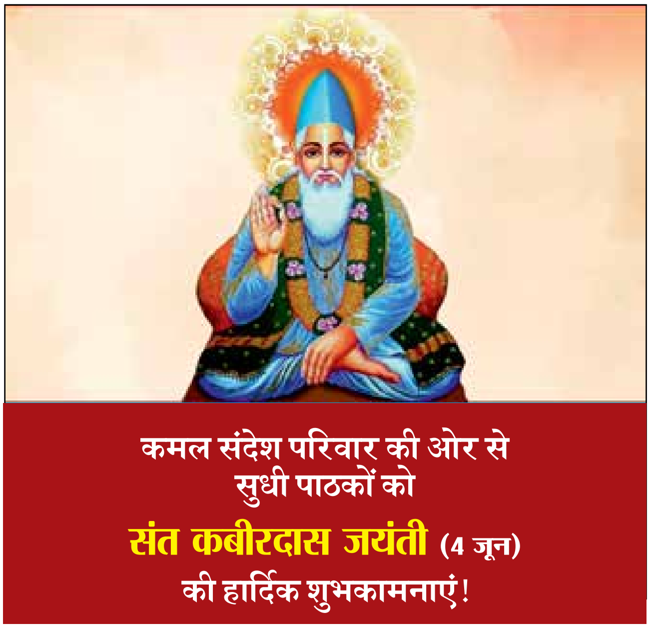

संपादकीय

वैश्विक उम्मीदों पर खरा उतरता भारत

आज जब पूरी दुनिया विभिन्न वैश्विक मंचों पर उभरते भारत की प्रशंसा कर रही है, हर भारतीय का हृदय एक उपलब्धि एवं संतुष्टि के भाव से आप्लावित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जापान, पापुआ न्यू गिनी एवं आस्ट्रेलिया के हाल के ही अत्यंत सफल दौरे से एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। यह वह युग है जिसमें भारत की गरिमा कई गुणा बढ़ गई है तथा इसे अब सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी देशों के मध्य शांति, सहयोग एवं भाईचारा पर बल देने से भारत के लिए सभी देशों के मन में सद्भाव का वातावरण तो बना ही है, साथ ही विश्व मीडिया में इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। आज भारत विभिन्न वैश्विक विषयों पर आगे बढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है; विभिन्न लक्ष्यों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर रहा है और कठिनाइयों से घिरे देशों की सहायता भी कर रहा है। यही नहीं, अनेक देशों की विकास यात्रा में अपने सहयोग के हाथ बढ़ा रहा है तथा देश में अविश्वसनीय कार्य कर पूरे विश्व की लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। पिछले नौ वर्षों में भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है- 'फ्रेजाइल-फाइव' अर्थव्यवस्था से आज विश्व की 'टॉप फाइव' अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके साथ ही विश्व की सबसे तेज विकास दर की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक मंदी के बीच एक 'ब्राइट-स्पॉट' के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौतियों का सामना किया तथा अनेक देशों के साथ उनकी परीक्षा की घड़ी में खड़ा रहा। इससे भारत की छवि एक आत्मविश्वास से भरे विश्वसनीय मित्र की बनी है।

> **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जापान, पापुआ न्यू गिनी एवं आस्ट्रेलिया के हाल के ही अत्यंत सफल दौरे से एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। यह वह युग है जिसमें भारत की गरिमा कई गुणा बढ़ गई है तथा इसे अब सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है**

क्वॉड, फिपिक एवं जी-7 में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चालीस कार्यक्रमों में भागीदारी की। इसमें सिडनी में हुए 20,000 से अधिक लोगों की भव्य सभा के अलावा विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के साथ ही कई द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों एवं सांस्कृतिक हस्तियों की बैठकों में पिछले नौ वर्षों में भारत में हुए व्यापक परिवर्तन, इसकी असीम संभावनाओं एवं सशक्त लोकतंत्र को सबने सराहा। वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की चमत्कृत कर देने वाली उपलब्धियों ने उन्हें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है जिसमें वे दूसरे नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं जब अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन प्रधानमंत्री श्री मोदी की लोकप्रियता का उल्लेख कर उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री श्री मारापे जब उनका स्वागत करते हुए पैर छू लेते हैं, तब हर भारतीय के मन में श्री मारापे के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। जब आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री श्री मोदी को 'द बॉस' कहते हैं तथा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस हिपकिंस उनसे मिलने के लिए हवाई यात्रा कर आस्ट्रेलिया आते हैं, हर भारतीय का हृदय आत्मगौरव तथा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की जनता के लिए आभार की भावना से भर उठता है। आज जब ये सभी राष्ट्र बांहे पसारे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी एवं फिजी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें अलंकृत कर रहे हैं तथा प्रधानमंत्री श्री मारापे उन्हें 'लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ' कह रहे हैं, तब भारत का बढ़ता वैश्विक कद एवं दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है।

हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शांति एवं सहयोग पर बल देते हुए भगवान बुद्ध एवं महात्मा गांधी के संदेश को रेखांकित किया। पापुआ न्यू गिनी के युवाओं को भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति से जोड़ने के लिए थिरुक्कुरल' की टोक पिसिन भाषा में अनुवाद का लोकार्पण करते हुए उन्होंने भारतीय सभ्यता के संदेश पर बल दिया। विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारतीय सांस्कृतिक एवं आदिवासी शिल्प की वस्तुएं भेंटकर प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान देते हुए उसका मान बढ़ाया है। जहां इस दौर से कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय आयामों को मजबूती मिली है, वहीं वैश्विक मंचों पर भारत के उदय से उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत की पहचान पुनः परिभाषित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सशक्त एवं करिश्माई नेतृत्व से पूरे विश्व में भारत के लिए नई क्षितिजों का निर्माण हो रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

जापान में जी-7 की बैठक

प्रधानमंत्री की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया यात्रा

प्रधानमंत्री ने जी-7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ कीं द्विपक्षीय बैठकें

'भारत, यूक्रेन संकट के समाधान हेतु बातचीत और कूटनीति का स्पष्ट समर्थन करता है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मई से 24 मई, 2023 तक तीन देशों— जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की छह दिवसीय यात्रा की। श्री मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में 20 मई को जी-7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा अनेक वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारापे के साथ 22 मई, 2023 को भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी की। यात्रा के आखिरी पड़ाव में श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, जहां पर उन्होंने सीईओ और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी बैठक की और सिडनी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय से मिले

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर 20 मई को हिरोशिमा शहर में जापानी अध्यक्षता के तहत जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के इतर श्री मोदी ने अनेक वैश्विक नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हिरोशिमा में 20 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भेंट की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष का पूरी दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हालांकि, यह उनके लिए कोई राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता का, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को आगे का रास्ता ढूंढ़ने के लिए बातचीत और कूटनीति को भारत द्वारा दिए गए स्पष्ट समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्थिति के समाधान के लिए भारत और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री अपने साधनों के भीतर सभी प्रयास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान

करना जारी रखेगा।

जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में 20 मई को जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों राजनेताओं ने अपने संबंधित जी-20 और जी-7 अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों के लिए तालमेल के तरीकों पर चर्चा की। श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों राजनेताओं ने समकालीन क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होते सहयोग पर भी चर्चा की।

राजनेताओं ने द्विपक्षीय विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर सहमति व्यक्त की। विचार-विमर्श में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ), हरित हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। आतंकवाद का मुकाबला करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी चर्चा हुई।

फ्रांस व कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में 20 मई को फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राजनेताओं ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, नागरिक उड्डयन; नवीकरणीय स्रोत; संस्कृति; रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन और विनिर्माण; असैन्य परमाणु सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा इस पर संतोष व्यक्त किया। वे नए क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए। राजनेताओं ने क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मई, 2023 को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण समारोह के दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों में प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और सांसद श्री नकातानी जेन, हिरोशिमा शहर के मेयर श्री कासुमी मत्सुई, हिरोशिमा सिटी असेम्बली के अध्यक्ष श्री ततसुनोरी मोतानी, हिरोशिमा के सांसद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, भारतीय समुदाय के सदस्य और जापान में महात्मा गांधी के अनुयायी शामिल थे।

19 से 21 मई तक होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई है।

पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री राम वनजी सुतार ने 42 इंच लंबी कांस्य प्रतिमा को तैयार किया है। मोतोयासु नदी से सटा यह स्थल प्रतिष्ठित ए-बम डोम के करीब है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से आते हैं।

इस स्थान को शांति और अहिंसा के लिए एकजुटता के प्रतीक के रूप में चुना गया है। महात्मा गांधी ने अपना जीवन शांति और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया। यह स्थान वास्तव में गांधीजी के सिद्धांतों और जीवन के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो दुनिया और नेताओं को प्रेरित करता है।

श्री मोदी ने 20 मई को हिरोशिमा में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री यून सुक येओल के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और विशेष रूप से व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, आईटी हार्डवेयर विनिर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

वियतनाम व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में 20 मई को वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री फाम मिन्ह चिन्ह से भेंट की। दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हासिल की गयी नियमित प्रगति को रेखांकित किया। राजनेताओं ने रक्षा क्षेत्र के अवसरों, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर भी चर्चा की। राजनेताओं ने क्षेत्रीय विकास पर विचारों का सकारात्मक आदान-प्रदान किया। उन्होंने आसियान और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की।

श्री मोदी ने हिरोशिमा में 21 मई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक से भेंट की। दोनों राजनेताओं ने भारत-यूके एफटीए वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लेने सहित अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। राजनेताओं ने व्यापार और निवेश, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा एवं दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध जैसे विस्तृत क्षेत्रों में सहयोग

को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की।

जी-7 शिखर सम्मेलन

जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मई को कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के विषय पर इस फोरम के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव फ़ूड सिस्टम का निर्माण, जिसमें विश्व के कमजोर लोगों लोगों खासकर सीमांत किसानों पर ध्यान केन्द्रित हो, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स पोषण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को एक साथ हल करता है। इस पर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। भोजन की बर्बादी की रोकथाम हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। यह स्थायी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा जी-20 और जी-7 के एजेंडा के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बनाने में लाभकारी होगी और ग्लोबल साउथ की आशाओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने मे सफल होगी।

जी-7 शिखर सम्मेलन के एक अन्य कार्य सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र ने कहा कि आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। अनेक संकटों से ग्रस्त विश्व में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से हैं। इन बड़ी चुनौतियों का सामना करने में एक बाधा यह है कि हम जलवायु परिवर्तन को केवल ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। हमें अपनी चर्चा का स्कोप बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में पृथ्वी को मां का दर्जा दिया गया है और इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए हमें पृथ्वी की पुकार सुननी होगी। उसके अनुरूप अपने आप को, अपने व्यवहार को बदलना होगा।

श्री मोदी ने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि भारत के लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और अपने दायित्वों को समझते हैं। सदियों से इस दायित्व का भाव हमारी रगों में बह रहा है। भारत सभी के साथ मिलकर अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (फिपिक) शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मई को भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (फिपिक) शिखर सम्मेलन में कहा कि तीसरे फिपिक समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे ख़ुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मारापे मेरे साथ इस समिट की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इस बार हम लम्बे समय के बाद मिल रहे हैं। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई चुनौतियों के कठिन दौर से गुज़रा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थीं। अब, नयी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खाद्य, ईंधन, उर्वरक और फार्मा की सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वह हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ : A Friend in need is friend indeed।

प्रधानमंत्री मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 22 मई, 2023 को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके वैश्विक नेतृत्व और ग्लोबल साउथ को लेकर उनकी पहल के लिए दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया गया। आज तक बहुत कम गैर-फिजी लोगों को यह सम्मान मिला है।

तीसरे भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी की हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू' से भी सम्मानित किया गया। श्री नरेन्द्र मोदी को यह पुरस्कार प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ पहल करने के लिए दिया गया।

प्रधानमंत्री को उनके 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अमेरिका, रूस और मध्य पूर्व सहित विभिन्न देशों ने सम्मानित किया है।

उन्होंने कहा कि मुझे ख़ुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां; गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फिपिक में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में हेल्थकेयर को बूस्ट करने के लिये हमने फ़िजी में एक सुपर-स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने का निर्णय किया है। प्रशिक्षित स्टाफ़, अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त यह अस्पताल पूरे क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन बनेगा। भारत सरकार इस मेगा ग्रीन-फील्ड प्रोजेक्ट का पूरा खर्च उठाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी 14 पेसिफिक आइलैंड देशों में डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-प्रशांत द्वीप-समूह सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन के दौरान 22 मई, 2023 को पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) के प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारापे के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करने और तीसरे एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मारापे को धन्यवाद दिया। दोनों राजनेताओं ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया तथा व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और कौशल विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों व उपायों पर चर्चा की।

उन्होंने जलवायु कार्रवाई से संबंधित मुद्दों और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की प्राथमिकताओं और इच्छाओं के लिए भारत के समर्थन और सम्मान को दोहराया।

श्री मोदी और प्रधानमंत्री श्री मारापे ने तमिल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' का पीएनजी की टोक पिसिन भाषा में अनुवाद लॉन्च किया। भाषाविद् श्रीमती सुभा ससींद्रन और पापुआ न्यू गिनी के वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर श्री शशिंद्रन मुथुवेल इस अनूदित पुस्तक के सह-लेखक हैं। पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री मारापे का प्राक्कथन है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लेखकों को बधाई दी और पापुआ न्यू गिनी में भारतीय विचार और संस्कृति के सिद्धांतों को संरक्षित करने में योगदान के लिए उनकी सराहना की।

प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज के साथ 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी के एडमिरल्टी हाउस में आगमन पर औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

दोनों नेताओं ने मार्च, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुए वार्षिक नेताओं के प्रथम शिखर सम्मेलन की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए बहुआयामी भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक एवं मज़बूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

विचार-विमर्श के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिजों, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था

क्वाड शिखर सम्मेलन

राजनेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकास के बारे में की महत्वपूर्ण बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मई को जापान के हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस, जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जोसेफ बाइडेन के साथ व्यक्तिगत उपस्थिति वाले तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

राजनेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकास के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत की, जिसने उनके साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक हितों की पुष्टि की। एक मुक्त, खुले और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण के तहत उन्होंने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को दोहराया। भारत-प्रशांत क्षेत्र की सहनीयता और समृद्धि को मजबूत करने के लिए राजनेताओं ने निम्न प्रमुख पहलों की घोषणा की, जो क्षेत्र की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद करेंगीः

- स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल, जो अनुसंधान और विकास में सुविधा प्रदान करेगी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा स्रोतों में बदलाव का समर्थन करेगी। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के विकास पर क्षेत्र के साथ जुड़ाव का मार्गदर्शन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े क्वाड सिद्धांतों को मंजूरी दी गई।
- महत्वपूर्ण नेटवर्कों को सुरक्षित और विविध बनाने के लिए समुद्र में केबल के डिजाइन, निर्माण, बिछाने और रखरखाव में क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए 'केबल संचार-संपर्क और सहनीयता के लिए साझेदारी।
- प्रशांत क्षेत्र में पहली बार पलाऊ में छोटे पैमाने पर ओआरएएन तैनाती के लिए क्वाड समर्थन। उन्होंने खुले, सह-संचालित और सुरक्षित टेलीकॉम प्लेटफॉर्म में उद्योग निवेश का समर्थन करने के लिए ओआरएएन सुरक्षा रिपोर्ट भी जारी की।
- राजनेताओं ने समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए भारत-प्रशांत साझेदारी की प्रगति का स्वागत किया, जिसकी घोषणा पिछले साल टोक्यो में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी। उन्होंने रेखांकित किया कि इस कार्यक्रम के तहत दक्षिण-पूर्व और प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों के साथ डेटा साझा किये जा रहे हैं और जल्द ही इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के भागीदारों को शामिल किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में मांग-संचालित विकास सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण कैसे इन प्रयासों में योगदान दे रहा है। राजनेताओं ने संयुक्त राष्ट्र, इसके चार्टर और इसकी एजेंसियों की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति जतायी। वे स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के विस्तार सहित बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने और इनमें सुधार करने के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमत हुए।
- राजनेताओं ने अपनी नियमित बातचीत जारी रखने और क्वाड संवाद की गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में श्री मोदी ने क्वाड नेताओं को 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत आने के लिए आमंत्रित किया। ■

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

ब्रिस्बेन में खोला जाएगा एक भारतीय वाणिज्य दूतावास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस के साथ 23 मई को सिडनी में कुडोस बैंक एरिना में भारतीय समुदाय के सदस्यों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। भारतीय प्रवासी समुदाय जिसमें छात्र, शोधकर्ता, पेशेवर व्यक्ति और व्यवसायी शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के कई मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से पश्चिमी सिडनी, जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, के परामट्टा स्थित हैरिस पार्क में निर्माण किये जाने वाले 'लिटिल इंडिया' गेटवे की आधारशिला का अनावरण किया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंधों की नींव के रूप में 'पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक सम्मान' पर प्रकाश डाला और दोनों देशों को जोड़ने वाले विभिन्न तत्वों को रेखांकित किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के योगदान और सफलता की सराहना की तथा उन्हें भारत का सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर बताया।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा कि पूरी दुनिया भारत की सफलता की गाथाओं में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखा रही है। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रगाढ़ हो रहे संबंधों पर चर्चा की और घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिस्बेन में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। ■

(एमएमपीए) पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। इससे छात्रों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों की गतिशीलता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें विशेष रूप से भारत के लिए बनाई गई मैट्स (प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था) नामक योजना का एक नवीन कुशल मार्ग शामिल है।

उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया, इससे स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्माण और इसके उपयोग में तेजी लाने जैसे अवसरों के लिए परामर्श मिल सकेगा। साथ ही, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र, ईंधन सेल्स पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा बुनियादी ढांचे और मानकों एवं विनियमों का समर्थन करेगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिस्बेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुकूल एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री अल्बनीज ने भारत की जी-20 अध्यक्षता और पहलों के प्रति ऑस्ट्रेलिया के मजबूत समर्थन को भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वह सितंबर, 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री अल्बनीज का स्वागत करने के लिए आशान्वित हैं। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्राः ऐतिहासिक और अत्यधिक सफल

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा इस बात का एक ठोस उदाहरण है कि पिछले 9 वर्षों में भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण और भारतीय मूल्यों, शासन व्यवस्था और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के प्रति सम्मान कैसे बढ़ा है। यह बात केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने 24 मई, 2023 को भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस वार्ता के प्रमुख बिंदुः

गर्मजोशी, प्रशंसा और सम्मान के क्षण

- यह यात्रा ऐसे उदाहरणों से भरपूर है, जो वैश्विक नेताओं के बीच भारत के लिए अपार सम्मान और सद्भावना का उदाहरण देती है।
- उस पल की विशिष्टता की कल्पना करें जब राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदीजी से ऑटोग्राफ मांगा, जब उन्होंने उनसे शिकायत की कि जब वे अमेरिका आते हैं तो रात्रिभोज में शामिल होने के लिए अनुरोधों की बाढ़ आ जाती है।
- पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे द्वारा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदीजी के विशिष्ट सम्मान के महत्व की कल्पना करें।
- प्रधानमंत्री अल्बनीज द्वारा प्रधानमंत्री मोदीजी को 'द बॉस' कहने और सिडनी ओपेरा हाउस को तिरंगे में रोशन करने के महत्व की कल्पना करें।
- कल्पना कीजिए कि न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने प्रधानमंत्री मोदीजी से विशेष रूप से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाकर किस सद्भावना का प्रदर्शन किया।
- ये ऐसे क्षण नहीं हैं जिन्हें इतिहास में अक्सर देखा जाता है। ये दुर्लभ घटनाएं हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए किए गए कठिन परिश्रम और प्रयासों का परिणाम हैं।
- ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी देश हर बात पर एक-दूसरे से या भारत से सहमत न हों।
- लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदीजी के महत्व की बात आती है तो इन सभी में एक आम सहमति दिखती है।

भारतीय संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार को बढ़ावा

- इस यात्रा के दौरान जो एक प्रमुख बात सामने आयी, वह यह थी कि प्रधानमंत्री मोदीजी ने भारतीय संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार को साझा करने के लिए वैश्विक मंचों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।
- महात्मा गांधी के लिए हिरोशिमा से अधिक उपयुक्त स्थान कोई नहीं हो सकता है और वहां गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके प्रधानमंत्री मोदीजी ने यह सुनिश्चित किया है कि गांधीजी का अहिंसा का संदेश हिरोशिमा जाने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचें। यह उन कई गांधी प्रतिमाओं में से एक है, जिनका उद्घाटन वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री मोदीजी ने किया है।
- पापुआ न्यू गिनी के युवाओं को भारतीय मूल्यों और संस्कृति से जोड़ने के लिए टोक पिसिन भाषा में तमिल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' का शुभारंभ।
- जी-7 और एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन में पुनर्नवीनीकरण वस्त्र पहनना, प्रधानमंत्रीजी के जी-20 में दिये गये मिशन लाइफ के संदेश का प्रतीक है।
- एफआईपीआईसी नेताओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में भारतीय व्यंजन और बाजरा आधारित वस्तुएं परोसी गयीं।
- उनके उपहार, भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति को विश्व नेताओं के बीच प्रचारित करने का एक प्रयास है।

भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चर्चा

- प्रधानमंत्री मोदीजी ने बातचीत के लिए उद्योग प्रमुखों से मुलाकात की और गोलमेज बैठक की। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के लिए अपने प्रयासों को मजबूती से आगे बढ़ाया।
- उन्होंने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, कलाकारों और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में उनसे मिलने वालों में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रायन पॉल श्मिट भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदीजी मेरे जीवनकाल में भारत के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक हैं। वह जिस व्यक्ति से भी मिलते है उससे पूर्ण दिलचस्पी से चर्चा करते है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हो या पहली बार मिलने वाला कोई व्यक्ति हो। विश्व स्तरीय वैज्ञानिक कार्य करने की भारत की क्षमता बहुत अधिक हो गई है।"
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर टोबी वॉल्श ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे असाधारण लोकतंत्र है। यूपीआई इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि भारत कैसे चीजों को स्वयं कर सकता है।

नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदीजी का भव्य स्वागत

जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नई दिल्ली आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, "जब भी मैं अपने देश की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बोलता हूं, मैं विश्व नेताओं की आंखों में देख कर अपनी बात रखता हूं और इसे बड़े गर्व के साथ साझा करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश के लोगों ने केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है।"

अपनी बैठकों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें 40 से अधिक विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि कैसे वे भारत की जी-20 अध्यक्षता को लेकर उत्साहित थे। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में शांति के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण का उल्लेख भी किया। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी की टोक पिसिन भाषा में 'द थिरुक्कुरल' के अनुदित संस्करण के विमोचन के बारे में भी बात की।

सिडनी में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम को याद करते हुए श्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से दूर रहने के विपक्षी दलों के फैसले पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "कार्यक्रम को पूरी दुनिया में देखा गया। यह न केवल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति के कारण विशेष था, बल्कि इस कार्यक्रम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और विपक्षी नेताओं की भागीदारी भी देखी गई। यह लोकतंत्र का शानदार प्रदर्शन था।"

विदेशों में कोविड टीके वितरित करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद मिली। उन्होंने कहा, "हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम बुद्ध और गांधी की भूमि से आते हैं। हम सद्भावना के प्रति समर्पित लोग हैं। दुनिया इसके लिए हमारा आभार व्यक्त कर रही है।" ■

कूटनीति और भारतीय डायस्पोरा

- प्रधानमंत्री मोदीजी ने 3 समिट- क्वाड, एफआईपीआईसी और जी-7 में हिस्सा लिया।
- 40 से अधिक कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री के लिए यह एक व्यस्त यात्रा थी।
- प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलनों के साथ-साथ द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से 2 दर्जन से अधिक विश्व नेताओं के साथ बातचीत की।
- सिडनी में कम्युनिटी इवेंट में करीब 20 हजार लोग शामिल हुए। अन्य नेताओं के विपरीत जो दूसरों को दोष देते हैं या देश को बदनाम करते हैं, प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से भारतीय आख्यानों पर केंद्रित था।
- जापान हो या पीएनजी या ऑस्ट्रेलिया, अखबार के पहले पन्ने अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री मोदीजी से संबंधित खबरों से भरे हुए थे। ■

भाजपा की उपस्थिति देश के सभी जगहों और सारे समाज में है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 एवं 18 मई, 2023 को महाराष्ट्र का दो दिवसीय प्रवास किया। पहले दिन उन्होंने पन्ना प्रमुख बैठक एवं विशाल लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया, जबकि दूसरे दिन 'युवा संवाद' कार्यक्रम एवं भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमिति के समापन सत्र को संबोधित किया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे के प्रथम दिन 17 मार्च, 2023 को मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित ठथाई भाटिया हॉल में आयोजित पन्ना प्रमुख बैठक को संबोधित किया।

श्री नड्डा ने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियों में किसी के पास नेता है, तो नीति नहीं, किसी के पास नीति है तो नियत नहीं और किसी के पास नियत है, तो नेता नहीं है। किसी के पास नेता, नीति और नियत है तो उनके पास वातावरण नहीं है। अगर किसी के पास ये सब कुछ है भी, तो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है, कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ता भी है, कैडर और ताकत भी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसकी उपस्थिति देश के सभी जगहों और सारे समाज में है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।

भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है, कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ता भी है, कैडर और ताकत भी है

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड और मास फालोइंग पार्टी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 9 करोड़ है, जबकी भाजपा की सदस्य संख्या उनसे दोगुनी अर्थात 18 करोड़ से भी ज्यादा है। 37 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भाजपा की इकाई है। 15,432 प्रखंडों में हमारी इकाई चल रही है, जबकि 1.16 लाख केन्द्रों पर भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केन्द्र है। 10.40 लाख बूथ में से 6.80 लाख बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति है। हमारे यहां बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक के बारे में विस्तृत बातें होती हैं। वर्तमान में देश के 15 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। केन्द्र में हमारी सरकार है। हमारे 303 सांसद लोकसभा में जबकि 93 सांसद राज्यसभा में हैं। देशभर में हमारे 1,385 विधायक हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में हमारे मेयर और हजारों की संख्या में कॉरपोरेटर्स हैं।

विशाल लाभार्थी सम्मेलन

'प्रधानमंत्री मोदीजी की नीतियों के कारण भारत की दुनिया में साख बढ़ी है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 मई, 2023 को घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड, मुंबई स्थित आरबीके हॉल में आयोजित विशाल लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी एवं महिलाओं के कल्याण के लिए उठाये जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़णवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले एवं मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोज कोटक सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, राज्य सरकार में मंत्री भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि सरकार जब सही नीतियों पर काम करती है तो किस तरीके से बदलाव आता है, यह पिछले 9 साल में देश की जनता ने अनुभव किया है। प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में पूरे देश में और महाराष्ट्र में श्री एकनाथ शिंदे एवं श्री देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व में हॉलिस्टिक और इन्क्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। आजादी के 70 साल बाद देश के गरीबों को यह महसूस हो रहा है कि केंद्र में उनकी सरकार है जो गरीबों की चिंता करती है और लास्ट माइल डिलीवरी को लेकर कटिबद्ध है।

> आजादी के 70 साल बाद देश के गरीबों को यह महसूस हो रहा है कि केंद्र में उनकी सरकार है जो गरीबों की चिंता करती है और लास्ट माइल डिलीवरी को लेकर कटिबद्ध है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण भारत की दुनिया में साख भी बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने माना है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण भारत में अत्यंत गरीबी की दर 1% से नीचे है। डीबीटी के माध्यम से श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अब तक लाभार्थियों के एकाउंट में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित कर चुकी है, वह भी बिना किसी बिचौलिए के। सरकार की तिजोरी से पैसा सीधे लाभार्थियों के एकाउंट में जा रहा है। आज हर महीने बिना किसी बिचौलिए के किसान सम्मान निधि के तहत हर चौथे महीने लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को दो-दो हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ नमो किसान सम्मान योजना भी चल रही है जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों को 6,000 रुपये सालाना अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस तरह, महाराष्ट्र में हर किसान को सालाना 12,000 रुपये मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत देश के लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग 83 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत योजना के साथ-साथ महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का भी लाभ लगभग दो करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है, उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं और अब तक लगभग 12 करोड़ घरों में टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो गेहूं/चावल और एक-एक किलो दाल दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी लगभग 6.53 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी विकास के बुनियादी आयामों पर कोई काम नहीं किया था। आखिर क्यों 2014 तक शौचालयों की अनदेखी की गई, महिलाओं के स्वास्थ्य की अनदेखी की गई, क्यों आजादी के 70 वर्षों बाद भी देश के 18 हजार से अधिक गांवों और 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, क्यों करोड़ों महिलाओं के पास गैस कनेक्शन नहीं था? आजादी के 70 सालों में पहली बार हुआ जब सही मायने में देश के गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला एवं युवाओं के सशक्तीकरण की शुरुआत हुई। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना को परास्त किया। भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन कर कोरोना पर काबू पाई है जबकि चीन सहित यूरोप और अमेरिका अब भी कोरोना की समस्या से दो-चार हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के बचाव अभियान की भी उन्होंने तारीफ़ की। 'आत्मनिर्भर' भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। कृषि क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

'युवा संवाद' कार्यक्रम

'युवा शक्ति राष्ट्र के सशक्तीकरण का एक मजबूत स्तंभ होता है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 मई, 2023 को रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई में आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया और युवाओं से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के यज्ञ में अपने आप को झोंक देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जारी विकास यात्रा की विस्तृत चर्चा करते हुए युवाओं के कल्याण हेतु किये जा रहे सरकार के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, सरकार में मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर एवं मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री आशीष शेलार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर अलग से कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया गया और 2015 में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। आज स्किल इंडिया मिशन से किस तरह युवाओं की प्रतिभा में निखार आया है और किस तरह वे आगे बढ़ रहे हैं, यह हम सब देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं। यूथ पावर का मतलब है एम्पॉवरिंग ऑफ नेशन। युवा शक्ति राष्ट्र के सशक्तीकरण का एक मजबूत स्तंभ होता है। कौशल विकास में भारत का भविष्य है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार मेला के माध्यम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। आपको यह जानकार ख़ुशी होगी कि अब तक पांच रोजगार मेलों के माध्यम से कुल 3.59 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से अब तक लगभग 1,36,850 युवाओं का कौशल विकास किया गया है जिसमें से लगभग 7,89,685 युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है। ग्रामीण ट्रेनिंग स्कूलों के माध्यम से लगभग 44 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई है जिसमें से लगभग 66 प्रतिशत महिलायें हैं। इसमें से लगभग 31 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 1.10 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। इसमें से लगभग 83 प्रतिशत सर्टिफाइड हो चुके हैं तथा 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। नेशनल आंत्रेप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम के तहत लगभग 21.40 लाख आंत्रेप्रेन्योर्स को विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम दिया गया।

भाजपा, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमिति बैठक

'हम लोग बदलाव के उपकरण हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 मई 2023 को जंगली महाराज रोड (शिवाजी नगर), पुणे (महाराष्ट्र) अवस्थित बालगंधर्व रंगमंदिर में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के समापन सत्र को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी एवं महिलाओं के कल्याण के लिए उठाये जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले, प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री देंवेंद्र फड़णवीस, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री श्री राव साहब दानवे, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती विजया राहटकर, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुनील देवधर, मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री आशीष शेलार, श्री सुधीर मुनंगटीवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, सह प्रभारी श्री जयभान सिंह पवैया सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, राज्य सरकार में मंत्री एवं सभी पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कार्यसमिति को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों से समाज को बहुत बड़ी आशाएं है। हम लोग एक प्रकार से बदलाव के उपकरण हैं। इसलिए हमें उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात सूत्र दिए हैं। पहला, सेवा भाव। कोरोना में सारी पार्टियां जहां कोरोन्टाइन हो गईं, आईसीयू मे चली गईं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्त्ता सेवा ही संगठन के नाम पर करोड़ों लोगों की मदद करने सड़कों पर उतर आए। यह सेवा भाव हमेशा जागृत रहना चाहिए। दूसरा, हमें संतुलन बिठाकर काम करना चाहिए। चौथा, हमें संयम के साथ काम करना चाहिए। परिवर्तन लाना है तो संयम रखना बहुत जरूरी है। पांचवां, हमें समाज में समन्वय बनाकर चलना चाहिए। छठा, हमारी सोच सदैव सकारात्मक और संवेदना से भरी होनी चाहिए। और सातवां, समाज के बीच संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। हम सब लोग बातें तो बहुत करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन संवाद कितना हो पाता है, इसका गहराई से चिंतना करना चाहिए। भाजपा के एक एक कार्यकर्त्ता को इन सातों मंत्रों को आत्मसात कर चलना चाहिए। ■

अब महिलायें बराबरी नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 मई, 2023 को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित महिला केंद्रित 15 फ्लैगशिप योजनाओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम 'कमल मित्र'का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मातृ सशक्तीकरण के लिए उठाये गए क़दमों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में मातृ सशक्तीकरण के जितने काम नहीं हुए, उससे कहीं अधिक कार्य विगत 9 वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। कार्यक्रम में श्री नड्डा के साथ भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन सहित महिला मोर्चा के सभी पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थीं। कार्यक्रम का लक्ष्य एक लाख कमल मित्र बनाने का है।

श्री नड्डा ने कहा कि काफी लंबे समय तक नीति निर्धारकों ने महिला सशक्तीकरण की बात तो की, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी में बहुत बड़ा गैप रहा। प्रधानमंत्रीजी लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस कर रहे हैं और अंतिम पायदान पर खड़ी अंतिम महिला तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में योजनाएं नीचे तक उतर रही हैं। फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। सुरक्षित मातृत्व की दिशा में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब जब महिलायें गर्भवती होती हैं तो उस दिन से लेकर उनकी गर्भावस्था के दौरान सभी तरह की जांच से लेकर सभी टीकाकरण, डिलवरी के पहले फ्री ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी के बाद फ्री ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ-साथ आर्थिक सहायता भी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। यदि इसके बाद भी कोई समस्या हो जाए तो उसे फिर से हॉस्पिटल लाकर इलाज करना, यह जिम्मेदारी भारत सरकार उठा रही है। साथ ही, नवजात शिशु का 12 तरह के टीकाकरण आदि की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार उठा रही है। कहना यह बहुत आसान है किंतु यह कितनी बड़ी योजना है और किस तरह जिम्मेवारी के साथ की जा रही है, यह अपने आप में एक मिसाल है।

श्री नड्डा ने जल जीवन मिशन की चर्चा करते हुए कहा कि 'हर घर नल से जल' दूर-दराज में रहने वाले लोगों को ताकत दे रहा है। इस योजना से महिला सशक्तीकरण हो रहा है। लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच रहा है। ज़रा सोचिये कि यदि 12 करोड़ घरों में नल से जल श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में पहुंचना शुरू हुआ है तो पहले क्या स्थिति होगी? इसी तरह उज्ज्वला योजना की बात करें तो यह केवल गैस कनेक्शन नहीं है बल्कि यह महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार लाने में सहायक हो रहा है। अब तक लगभग 9.5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है।

महिला सशक्तीकरण में सहायक श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कौशल विकास योजना के माध्यम से लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं को सर्टिफिकेट मिला है। मुद्रा योजना का लगभग 68 प्रतिशत लाभ महिलाओं को मिला है। स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम का लगभग 81 प्रतिशत लाभ मातृशक्ति को हुआ है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में लगभग 55 प्रतिशत एकाउंट महिलाओं के खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 58 प्रतिशत घरों का मालिकाना हक़ अब महिलाओं के पास है। भारत में पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में महिलाओं को डिफेंस में परमानेंट कमीशन मिलना शुरू हुआ है। अब डिफेंस में महिलाओं को कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को एडमिशन मिलना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज महिलायें किसी से कम नहीं हैं। अब महिलायें बराबरी नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ■

भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी 17 मेयर सीटों पर शानदार जीत हासिल की

पार्टी ने अधिकांश नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में विजय हासिल की

भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की और मेयर पदों की सभी 17 सीटों और कुल 1420 में से 813 पार्षद सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा को नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद् के चुनावों में भी जबरदस्त जीत मिली, जिसके परिणाम 13 मई, 2023 को घोषित किए गए थे। इस जीत के साथ भाजपा ने 2017 की तुलना में अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है, जब पार्टी के 14 मेयर, 596 पार्षद सदस्य, 923 नगरपालिका सदस्य और 664 नगर पंचायत सदस्य विजयी हुए थे। समाजवादी पार्टी ने अपने दूसरे स्थान को बरकरार रखा, जबकि बसपा तीसरे स्थान पर रही।

पार्टी के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य में 'सुशासन, विकास और भयमुक्त वातावरण' को जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने 2017 की तुलना में अधिक सीटें जीती हैं।

आंकड़ों के अनुसार, आगरा नगर निगम से — श्रीमती हेमलता दिवाकर, अलीगढ़ से — श्री प्रशांत सिंघल, अयोध्या से— श्री गिरीशपति त्रिपाठी, बरेली से — श्री उमेश गौतम, फिरोजाबाद से — श्रीमती कामिनी राठौर, गाजियाबाद से — श्रीमती सुनीता दयाल, गोरखपुर से —डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, झांसी से — श्री बिहारी लाल आर्य, कानपुर से —श्रीमती प्रमिला पाण्डेय, लखनऊ से — श्रीमती सुषमा खर्कवाल, मेरठ से — श्री हरिकांत अहलूवालिया, मुरादाबाद से — श्री विनोद अग्रवाल, प्रयागराज से — श्री गणेश केसरवानी, सहारनपुर से — डॉ. अजय कुमार सिंह, शाहजहांपुर से — श्रीमती अर्चना वर्मा, वाराणसी से — श्री अशोक तिवारी, मथुरा—वृंदावन से — श्री विनोद अग्रवाल मेयर पद पर विजयी हुए। भाजपा के 17 मेयर में से तीन लगातार दूसरी बार चुने गए हैं।

अन्य स्थानीय निकायों में देखें तो भाजपा ने नगरपालिका परिषद् में 1360 वार्ड सदस्यों के साथ 89 अध्यक्षीय सीटें जीती हैं, ऐसे ही नगर पंचायतों में 1403 वार्ड सदस्यों साहित 191 अध्यक्षीय सीटों पर जीत हासिल की।

जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित जश्न कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका पुष्प गुच्छ से अभिनंदन किया गया और मिठाइयां बांटीं गयीं। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के लिए 'भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और पार्टी एवं सरकार के बीच अच्छे समन्वय' को महत्त्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 'सुशासन, विकास और सुरक्षा' को जनादेश दिया है, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

जहां तक विपक्षी दलों की बात है तो 2017 में मेयर की दो सीटें (मेरठ और अलीगढ़) जीतने वाली बसपा इस बार एक भी

'अभूतपूर्व विकास को लेकर जन-जन के समर्थन की अभिव्यक्ति'

निकाय चुनावों में इस शानदार विजय के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत-बहुत बधाई। यह सफलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन-जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है।

'जनता के विश्वास की जीत'

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी और उत्तर प्रदेश भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। यह विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में क्रियान्वित हो रही समावेशी व कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है।

मेयर सीट नहीं जीत सकी। पार्टी ने नगर निगमों में नगरसेवकों की केवल 85 सीटों, अध्यक्षों की 16 सीटों और नगरपालिका परिषदों में 191 सदस्यों की जीत हासिल की।

2017 की तरह मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी ने नगर निगमों में नगरसेवकों की 191 सीटों, अध्यक्षों की 35 सीटों और नगरपालिका परिषदों में 425 सदस्यों की जीत हासिल की थी। नगर पंचायतों में पार्टी ने 79 अध्यक्षों और 485 सदस्यों की सीटें जीतीं।

कांग्रेस को नगर निगम पार्षदों की केवल 77 सीटों, 91 सदस्यों वाली नगर पालिका अध्यक्ष की चार सीटों और 77 सदस्यों वाली नगर पंचायत अध्यक्षों की 14 सीट ही मिली हैं। ■

हम आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे: प्रधानमंत्री

कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम 13 मई, 2023 को घोषित किये गये। भाजपा ने अपने 2018 के प्रदर्शन 36 प्रतिशत वोट शेयर को बरकरार रखा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 4.8 प्रतिशत अतिरिक्त वोट मिले, कांग्रेस को कुल 42.9 प्रतिशत वोट मिले। जद (एस) को इस बार 5 प्रतिशत वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ और निर्दलीय उम्मीदवारों को 5.2 प्रतिशत वोट शेयर मिले और दो निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए।

परिणामों की घोषणा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 135 सीटें हासिल हुई, जबकि भाजपा को 66 सीटें मिलीं और जद (एस) को 19 सीटें मिलीं। नवनिर्वाचित विधानसभा में कांग्रेस की चार महिला विधायक, भाजपा की तीन, जद (एस) की दो और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं।

बेंगलुरु क्षेत्र में भाजपा ने अपने वोट शेयर में महत्वपूर्ण सुधार किया और पार्टी को यहां 41.2 प्रतिशत वोट मिले। भाजपा ने बेंगलुरु डिवीजन में अपनी सीटों की संख्या 11 से बढ़ाकर 17 की और पार्टी का वोट शेयर 35.8 प्रतिशत से बढ़कर 41.2 प्रतिशत हो गया।

कर्नाटक परिणाम स्थिति			
224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 224 की ज्ञात स्थिति			
दल का नाम	विजयी	आगे	कुल
भारतीय जनता पार्टी	66	0	66
निर्दलीय	2	0	2
इंडियन नेशनल कांग्रेस	135	0	135
जनता दल (सेक्युलर)	19	0	19
कल्याणा राज्य प्रगती पक्ष	1	0	1
सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	1	0	1
कुल	224	0	224

दलवार मत हिस्सेदारी

कृपया और अधिक विवरण देखने के लिए अपना माउस चार्ट या लीजेंड के ऊपर मूव करें।
(मत %, मत गणना)

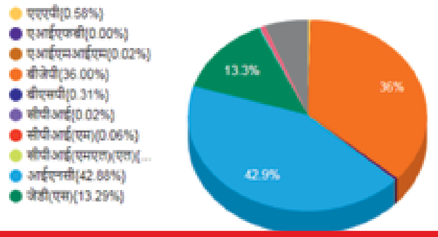

कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम-2023

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

आगे उन्होंने कहा, 'मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, "भाजपा कर्नाटक की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। मैं कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों और हमारे दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले लोगों को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाकर अपनी आवाज बुलंद करेगी।"

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई, 2023 को हुआ था और चुनाव परिणाम 13 मई को जारी किए गए थे। राज्य की 224 सीटों पर वोट डाले गये और 72.67 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ■

कैबिनेट ने उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को दी मंजूरी

किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया तथा सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई को रबी मौसम 2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक) के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी और खरीफ मौसम, 2023 (1.4.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए अनुमोदित एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी।

एनबीएस योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से नियंत्रित है। केंद्र सरकार ने रबी 2022-2023 के लिए 01.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावी एनबीएस दरों में संशोधन को मंजूरी दी और खरीफ, 2023 (01.04.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी, ताकि किसानों को रियायती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें।

सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।

कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 को दी स्वीकृति

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17 प्रतिशत सीएजीआर के साथ लगातार वृद्धि की है। इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख मानदंड को पार किया है। यहां 105 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) का उत्पादन हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई को 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17 प्रतिशत सीएजीआर के साथ लगातार वृद्धि की है। इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख मानदंड को पार किया है। यहां 105 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) का उत्पादन हुआ।

भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इस वर्ष 11 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 90 हजार करोड़ रुपये) का मोबाइल फोन का निर्यात किया गया। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारत में आ रहा है और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है।

दरअसल, मोबाइल फोन के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की सफलता को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के पीएलआई योजना 2.0 को स्वीकृति दी।

मुख्य विशेषता

- सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की पीएलआई योजना 2.0 के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस आते है।
- इस योजना का बजटीय परिव्यय 17,000 करोड़ रुपये है।
- इस योजना की अवधि 6 वर्ष है।
- अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन 3.35 लाख करोड़ रुपये है।
- अनुमानित वृद्धिशील निवेश 2,430 करोड़ रुपये है।
- अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 है।

महत्त्व

भारत सभी वैश्विक कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला भागीदार के रूप में उभर रहा है। बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर कंपनियों ने भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है। यह देश के भीतर बड़ी मांग रखने वाले मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग द्वारा समर्थित है। अधिकांश प्रमुख कंपनियां भारत में स्थित सुविधा से भारत के भीतर घरेलू बाजारों की आपूर्ति करना चाहती हैं और भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना चाहती हैं। ■

शून्य से नीचे पहुंची थोक महंगाई दर, खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी आई कमी

थोक महंगाई में भारी गिरावट आई है। जुलाई, 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि थोक महंगाई दर शून्य से नीचे गिर गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अप्रैल, 2023 महीने के लिए (अप्रैल, 2022 महीने की तुलना में) -0.92 प्रतिशत (अनंतिम) है जबकि मार्च, 2023 में यह 1.34 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

अप्रैल, 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से मूलभूत धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों, गैर खाद्य वस्तुओं, रसायन एवं रसायन उत्पादों खनिज तेलों, रबर और प्लास्टिक उत्पादों तथा कागज एवं कागज उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण आई है।

डब्ल्यूपीआई के प्रमुख समूहों में महीना-दर-महीना बदलाव

प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62%)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक मार्च, 2023 के 175.0 (अनंतिम) से अप्रैल, 2023 में 1.31% बढ़कर 177.3 (अनंतिम) हो गया। मार्च, 2023 की तुलना में अप्रैल, 2023 में कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतें (3.47%), खनिज (2.30%) और खाद्य सामग्री (1.45%) के मूल्यों में वृद्धि हुई। मार्च, 2023 की तुलना में अप्रैल, 2023 में गैर-खाद्य पदार्थों की कीमतों (-0.66%) में गिरावट आई।

ईंधन और बिजली (भार 13.15%)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक मार्च, 2023 के 156.8 (अनंतिम) से अप्रैल, 2023 में 2.68% घटकर 152.6 (अनंतिम) हो गया। मार्च, 2023 की तुलना में अप्रैल, 2023 में कोयला (-0.22%) बिजली (-2.20%) और खनिज तेल (-3.33%) की कीमतों में गिरावट आई।

निर्मित उत्पाद (भार 64.23%)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक अप्रैल, 2023 में 141.2 (अनंतिम) पर अपरिवर्तित रहा। वे समूह जिनकी कीमतों में मार्च, 2023 की तुलना में अप्रैल, 2023 में कमी देखी गई, इनमें रसायन और रासायनिक उत्पाद; बुनियादी धातु; खाद्य उत्पाद; मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद; चमड़ा और संबंधित उत्पाद; कागज और कागज उत्पाद आदि शामिल हैं।

डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38%)

प्राथमिक वस्तु समूह से 'खाद्य वस्तुएं' और निर्मित उत्पाद समूह से 'खाद्य उत्पाद' वाला खाद्य सूचकांक मार्च, 2023 में 172.1 से बढ़कर अप्रैल, 2023 में 173.6 हो गया। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च, 2023 में 2.32% से घटकर अप्रैल, 2023 में 0.17% हो गई। ■

समय सीमा के पूर्व ही 50 हजार से अधिक अमृत सरोवरों का हुआ निर्माण

अब तक 59,282 उपयोगकर्ता समूह सरोवरों के रखरखाव और उससे अपनी आजीविका सृजन के लिए मिशन अमृत सरोवर से जुड़ चुके हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भविष्य के लिए जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और विकास करना है। कुल मिलाकर, इस मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त, 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे निर्धारित समय सीमा के पूर्व प्राप्त कर लिया गया। अब तक 50,071 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में जिला प्रशासन, पंचायतराज पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न संस्थानों के समन्वित प्रयासों और आमजनों की भागीदारी से 10 मई, 2023 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 1,05,243 स्थलों की पहचान की गई, जिनमें से 72,297 स्थलों पर काम शुरु किया गया। अब तक 50,071 हजार अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है।

मिशन अमृत सरोवर का ध्येय यह भी है कि सरोवरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार इस तरह किया जाय कि वे स्थानीय सामुदायिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाए। सरोवरों के रखरखाव में समुदाय का स्वामित्व हो, ताकि उनका दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस हेतु प्रत्येक सरोवर के लिए उपयोगकर्ता समूह का गठन किया जा रहा है। अब तक 59,282 उपयोगकर्ता समूह सरोवरों के रखरखाव और उससे अपनी आजीविका सृजन के लिए मिशन अमृत सरोवर से जुड़ चुके हैं। ■

सैन्य महत्व के 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट/सब-सिस्टम्स/स्पेयर एंड कंपोनेंट्स की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मिली मंजूरी

अब तक देश में 1,238 (प्रथम सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-262, द्वितीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-11, तृतीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-37) में से 310 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (एलआरयू)/सब-सिस्टम्स/कल-पुर्जों और कंपोनेंट्स, हाई-ऍंड-मटीरियल्स और अतिरिक्त-उत्पाद सहित 715 करोड़ रुपए मूल्य के आयात प्रतिस्थापन मूल्य वाली की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) को मंजूरी दे दी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 मई को जारी एक बयान के अनुसार पीआईएल की एलआरयू/सबसिस्टम/असेम्बली/सब-असेंबली/अतिरिक्त कंपोनेंट्स से जुड़ी यह चौथी सूची उन तीन पीआईएल की श्रृंखला की निरंतरता में है जिसका मुद्रण दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में क्रम से किया गया था। इन सूचियों में 2500 आइटम हैं जो पहले से ही स्वदेशी हैं और 1238 (351+107+780) आइटम वे हैं जो दी गई समय सीमा के भीतर स्वदेशी किए जाएंगे।

अब तक देश में 1,238 (प्रथम सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-262, द्वितीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-11, तृतीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-37) में से 310 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इस स्वदेशीकरण को विभिन्न साधनों के माध्यम से पूरा करेंगे। कुछ को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के द्वारा विकसित और निजी भारतीय उद्योग द्वारा बनाया जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था में विकास, रक्षा-क्षेत्र में निवेश और रक्षा के सार्वजनिक उपक्रमों के आयात में कमी आयेगी। इसके साथ ही घरेलू रक्षा-उद्योग में अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के शामिल होने से रक्षा उपकरणों के डिजाइन क्षमता भी बढ़ेगी। ■

728 रेलवे स्टेशनों को 785 'एक स्टेशन एक उत्पाद' बिक्री केन्द्र के रूप में किया गया शामिल

इसका उद्देश्य 'वोकल फॉर लोकल' विजन को बढ़ावा देना और स्थानीय/स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है

रेल मंत्रालय ने भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' विजन को बढ़ावा देने, स्थानीय/स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करने तथा समाज के वंचितों वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (ओएसओपी) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी केन्द्रों को स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और उच्च दृश्यता प्रदान करने के लिए आवंटित किया जाता है।

रेल मंत्रालय द्वारा 12 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इसकी पायलट योजना 25.03.2022 को शुरू की गई थी और 01.05.2023 के अनुसार पूरे देश के 21 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 785 ओएसओपी केन्द्रों के साथ 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इन ओएसओपी स्टालों को एकरूपता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के माध्यम से डिजाइन किया गया है। मार्च, 2022 से 01.05.2023 तक संचयी प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या 25,109 हो गई है।

'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' स्थान विशेष के लिए विशिष्ट हैं और इसमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, स्थानीय बुनकरों द्वारा हथकरघा, विश्व प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी जैसे हस्तशिल्प, कपड़े पर चिकनकारी और जरी-जरदोजी का काम या मसाले चाय, कॉफी और अन्य संसाधित/अर्द्ध संसाधित खाद्य पदार्थ/उत्पाद जिनका देश में उत्पादन हुआ है, शामिल हैं।

उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में असमिया पीठा, पारंपरिक राजबंशी पोशाक, झापी, स्थानीय कपड़ा, जूट उत्पाद (टोपी, गमछा, गुड़िया) ओएसओपी स्टालों पर उपलब्ध हैं और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र, कश्मीरी गिरदा, कश्मीरी कहवा और सूखे मेवे प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत में काजू उत्पाद, मसाले, चिन्नालापट्टी हथकरघा साड़ियां यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, देश के पश्चिमी भाग में कढ़ाई और ज़री ज़रदोज़ी, नारियल हलवा, स्थानीय रूप से उगाए गए फल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बंधनी प्रसिद्ध हैं।

इस योजना के तहत उत्पाद श्रेणियों में निम्न वस्तुएं शामिल हैं:

- हस्तशिल्प/कलाकृतियां
- कपड़ा और हथकरघा
- पारंपरिक वस्त्र
- स्थानीय कृषि उत्पाद (बाजरा सहित)/प्रसंस्कृत/अर्द्ध प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ■

प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित

रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां केंद्र सरकार के विभागों और इस पहल का समर्थन करने वाले राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भर्तियां की गयीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया तथा विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने गुजरात जैसे राज्यों में हाल के रोजगार मेलों और असम के आगामी मेले को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और भाजपाशासित राज्यों में इन मेलों का आयोजन युवाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है और इसे तेज़, पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया है। भर्ती प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड, नई भर्तियों को शामिल करने में मोटे तौर पर 15-18 महीने का समय लेता था, जबकि आज इसमें केवल 6-8 महीने लगते हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि पहले की कठिन भर्ती प्रक्रिया में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते थे और फिर इन्हें डाक के माध्यम से जमा किया जाता था, लेकिन अब इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये सरल बनाया गया है, जिसके लिए दस्तावेजों के स्व-सत्यापन का प्रावधान भी पेश किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि समूह 'सी' और समूह 'डी' के लिए साक्षात्कार भी समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा पूरी प्रक्रिया से भाई-भतीजावाद की समाप्ति है।

उल्लेखनीय है कि रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां केंद्र सरकार के विभागों और इस पहल का समर्थन करने वाले राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भर्तियां की गयीं।

देश भर से चयनित नवनियुक्त कर्मी; ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक-सह-टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक-सह-टाइपिस्ट, कनिष्ठ लेखा लिपिक, रेल लाइन देखभाल कर्मी, सहायक अनुभाग अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उप मंडल अधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, फायरमैन, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, मंडल लेखाकार, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक प्रोफेसर जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्त होंगे।

दरअसल, रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तीकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

नवनियुक्त कर्मियों को 'कर्मयोगी प्रारंभ', जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है, के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। ■

मार्च, 2023 के महीने में ईएसआई योजना के तहत जोड़े गए 17.31 लाख नए कर्मचारी

ईएसआईसी के प्रारंभिक वेतन संबंधी आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2023 के महीने में 17.31 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 मई को जारी एक बयान के मुताबिक मार्च, 2023 के महीने में लगभग 19,000 नए संस्थानों को पंजीकृत किया गया और ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा छत्र के तहत लाया गया, जिससे अधिक कवरेज सुनिश्चित होती है।

आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि देश के युवाओं के लिए अधिक नौकरियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि महीने के कुल 17.31 लाख कर्मचारियों में से 25 वर्ष तक के आयु समूह वाले 8.26 लाख कर्मचारी नए पंजीकरणों का अधिकतम हिस्सा हैं, जो कि जुड़ने वाले कुल कर्मचारियों का 48 प्रतिशत हैं।

मार्च, 2023 के वेतन आंकड़ों के लिंगानुसार विश्लेषण के मुताबिक 3.36 लाख महिला सदस्य भी इसमें शामिल हो चुकी है। इसके अलावा, मार्च, 2023 के महीने में कुल 41 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ईएसआई योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं। यह दिखाता है कि ईएसआईसी समाज के हर वर्ग को अपने लाभ प्रदान करने के प्रति समर्पित है। ■

'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में उपलब्ध नल से जल

पूरे देश भर में 9.06 लाख स्कूलों और 9.39 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया तथा 'जल जीवन मिशन' के तहत आर्सेनिक/फ्लोराइड संदूषण वाली 22,016 बस्तियों में अब सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है

आजादी के अमृत काल के तहत 'जल जीवन मिशन' (जेजेएम) देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की एक नई उपलब्धि का जश्न मना रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की उपलब्धि की सराहना की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! यह अत्यंत खुशी की बात है कि गांवों और गरीबों तक हर जरूरी सुविधा पहुंचाने के हमारे प्रयासों के सुपरिणाम निरंतर सामने आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जेजेएम के लॉन्च की घोषणा के समय गांवों में केवल 3.23 करोड़ (16.64%) घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध था।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 16 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब) तथा 3 केंद्रशासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह) ने इसकी 100% कवरेज की सूचना दी है।

केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में 9.06 लाख (88.55%) स्कूलों और 9.39 लाख (84%) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। हमारे देश के 112 आकांक्षी जिलों में मिशन के लॉन्च के समय केवल 21.64 लाख (7.84%) घरों में नल का पानी उपलब्ध था, जो अब बढ़कर 1.67 करोड़ (60.51%) हो गया है।

जेजेएम ग्रामीण आबादी को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है। नियमित रूप से नल के पानी की आपूर्ति से लोगों को विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों को अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की भारी बाल्टी भरकर ले जाने से राहत मिलती है, जिससे सदियों पुरानी उनकी मेहनत कम हो जाती है।

देश में 5.24 लाख से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियों का गठन किया गया है और 5.12 लाख ग्रामीण कार्य योजनाएं (वीएपी) तैयार की गई हैं, जिसमें पेयजल स्रोत वृद्धि, ग्रेवाटर उपचार और इसके पुनः उपयोग और गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों का नियमित संचालन और रखरखाव आदि योजनाएं शामिल हैं।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय 22,016 बस्तियां (आर्सेनिक-14,020, फ्लोराइड-7,996), जिनकी 1.79 करोड़ आबादी (आर्सेनिक-1.19 करोड़, फ्लोराइड-0.59 करोड़) पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक/फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित थीं। जैसाकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बताया गया है, अब सभी आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। ■

संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ, घर बैठे ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे चोरी हुआ फोन

मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे विभिन्न धोखे भी हो सकते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है

उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई को संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया।

श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आज तीन सुधार किए जा रहे हैं:

- सीईआईआर (सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर) - चोरी/खोए मोबाइल ब्लॉक करने के लिए।
- अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें - अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए।
- एएसटीआर (टेलीकॉम सिम ग्राहक सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन)- धोखाधड़ी करने वाले सब्सक्राइबर्स की पहचान करने के लिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे विभिन्न धोखे भी हो सकते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता सुरक्षा ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

संचार साथी पोर्टल का उपयोग करके अब तक धोखाधड़ी करने वाले 40 लाख से अधिक कनेक्शन की पहचान की गई है और 36 लाख से अधिक ऐसे जुड़ावों को अब तक बंद कर दिया गया है। ■

मोदी स्टोरी

स्वच्छता से कोई समझौता नहीं: दशकों पहले मोदीजी की पहल

— अशोक भट्ट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश स्वच्छता की नई कहानियां लिख रहा है, देखा जाए तो स्वच्छता के लिए उनका संकल्प बचपन से ही है और वह हमेशा स्वच्छ परिवेश के प्रति संकल्पित रहे। स्कूल में प्रवेश करने से पहले जूते को कपड़े के टुकड़े से साफ करने से लेकर पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाने तक श्री नरेन्द्र मोदी का स्वच्छता का संकल्प उनके लिए हमेशा ताकत रहा है।

उनके युवा दिनों की एक घटना है जिसे कई लोग आज स्वच्छ भारत अभियान की नींव के रूप में देखते हैं।

यह वर्ष 1989 की बात है, श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में जूनागढ़ आ रहे थे। उन्हें जूनागढ़ पार्टी कार्यालय में जिला स्तर के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना था। जूनागढ़ में भाजपा कार्यालय शहर के बाहरी इलाके में था, यह वास्तव में आचार्य जी का निवास था जिसे बाद में पार्टी कार्यालय में बदल दिया गया था।

चूंकि कार्यालय शहर के बाहरी इलाके में था, इसलिए कोई भी कर्मचारी वहां रोजाना जाकर सफाई नहीं करता था। जब भी कोई मीटिंग होती थी तो कुछ कार्यकर्ता सुबह ऑफिस आते थे, साफ-सफाई करते थे, कुछ इंतजाम करते थे और फिर मीटिंग होती थी। लेकिन इस बार श्री नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था।

श्री मोदी ने एक पार्टी कार्यकर्ता श्री अशोक भट्ट से उन्हें कार्यालय ले जाने का आग्रह किया। श्री भट्ट उन्हें अपने स्कूटर पर कार्यालय ले गए। जब श्री मोदी ने श्री भट्ट के साथ पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया, तो उन्होंने एक गंदा कार्यालय देखा। यूं तो उन्होंने श्री भट्ट से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसे एक झाड़ू लाने का आग्रह किया। श्री भट्ट ने समझाने की कोशिश की कि 2-3 दिन से कार्यालय में कोई नहीं आया था इसलिए कार्यालय गंदा है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और फिर से झाड़ू के लिए कहा।

श्री भट्ट ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एक गंदे पार्टी कार्यालय से खुश नहीं थे। फिर उन्होंने श्री मोदी को एक तरफ खड़े होने को कहा और वहां कार्यालय की सफाई कराई।

श्री अशोक भट्ट और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता अब श्री नरेन्द्र मोदी के साथ ऐसी घटनाओं को याद करते हैं और महसूस करते हैं कि स्वच्छ भारत की नींव दशकों पहले पड़ गयी थी और उस दौरान भी प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वच्छता को लेकर उतने ही चिंतित थे। ■

केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर का किया शिलान्यास

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 20 मई को गुजरात के द्वारका में 470 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया।

अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि विषम मौसम और भौगोलिक परिस्थिति में तटीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 450 एकड़ से अधिक भूमि पर राष्ट्रीय कोस्टल पुलिस अकादमी बनाने की आज शुरुआत यहां की गई है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और देश की सीमाओं की सुरक्षा मज़बूत हुई हैं और सीमाओं और देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं।

श्री शाह ने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेशनल कोस्टल पुलिस अकादमी को मंजूरी दी और इसे श्री कृष्ण की नगरी में स्थापित करने का निर्णय किया गया। श्री शाह ने कहा कि पूरे देश में कुल तटीय पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 12 हज़ार है और इस अकादमी के पूरी तरह परिचालन में आने के बाद यहां एक साल में 3,000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। ■

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा

अटल बिहारी वाजपेयी

मुंबई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय परिषद् में 28 दिसंबर, 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण का चौथा भाग—

चुनाव- एक बड़ा जुआ

चुनाव पद्धति कितनी विचित्र है—इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि यद्यपि 1971 में कांग्रेस को भी ठीक उतने ही वोट मिले थे, जितने 1977 में जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे, फिर भी 43.06 प्रतिशत वोट के बल पर 1971 में कांग्रेस को लोकसभा की 350 सीटें मिली थीं, जबकि जनता पार्टी को 298 स्थान ही प्राप्त हुए। 1980 में कांग्रेस (आई) 42.57 प्रतिशत वोटों के बल पर 66.86 प्रतिशत स्थान ले गई, जबकि 1977 में जनता को 43.06 प्रतिशत वोटों के आधार पर केवल 56.80 प्रतिशत स्थान ही 'लोकसभा' में मिले। कम वोटों के आधार पर अधिक सीटें मिलने का दृश्य 1952 से ही दिख रहा है। ब्रिटेन में इस चुनाव पद्धति के आलोचकों ने कहा है कि इसमें चुनाव एक बड़े जुए का रूप धारण कर लेता है।

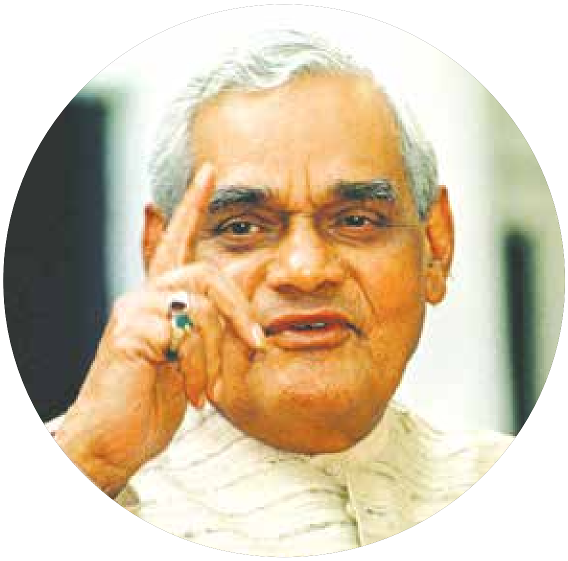

नई चुनाव प्रणाली की आवश्यकता

स्पष्ट है कि वर्तमान चुनाव पद्धति दोषपूर्ण है और वह बहुसंख्या की राय को प्रतिबिंबित नहीं करती। राजनीतिक दल सीटों के बल पर यह गर्वोक्ति करते नहीं थकते कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है, किंतु यह तथ्य बना रहता है कि देश के भीतर उन्हें अल्पमत का ही समर्थन है। संसद् या विधानमंडलों में बहुमत के आधार पर महत्त्वपूर्ण फैसले तो कर लिये जाते हैं, कानून भी बनाए जाते हैं, संविधान में भी मूलगामी संशोधन कर दिए जाते हैं, किंतु इनके पीछे बहुमत का समर्थन नहीं होता। यह आवश्यक है कि गत चुनाव परिणामों के प्रकाश में हम चुनाव पद्धति में शीघ्र ही कुछ बुनियादी परिवर्तन करें। वर्तमान बहुमत प्रणाली के स्थान पर हमें सूची पद्धति का अवलंबन करना चाहिए, जो यूरोप के अधिकतर लोकतंत्रवादी देशों में सफलतापूर्वक चल रही है। सूची पद्धति मतदाताओं को जाति और संप्रदाय की संकुचित परिधियों से निकालकर उन्हें दलों की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ देगी। इससे दलों का बिखराव रुकेगा और दलबदल पर अंकुश लगेगा। चुनाव एक जुआ नहीं रहेगा। संसद तथा विधानमंडलों में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व मोटे तौर पर उन्हें प्राप्त जन समर्थन के अनुरूप होगा। बहुमत प्रणाली के कुछ लाभ अवश्य हैं। एक चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि अपने विकास की ओर अधिक अच्छी तरह से ध्यान दे सकता है। पश्चिम जर्मनी ने दोनों पद्धतियों की अच्छाइयों का समावेश कर एक मिश्रित प्रणाली का विकास किया है। अच्छा होगा कि हम लोकसभा के लिए सूची पद्धति तथा विधानसभाओं के लिए संयुक्त पद्धति का अवलंबन करें।

चुनाव कानूनों में संशोधन के लिए निर्मित संयुक्त संसदीय समिति ने 1973 में यह सिफारिश की थी कि देश में सूची पद्धति लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। यह खेद का विषय है कि उस सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस मामले में जनता सरकार का दामन भी बेदाग नहीं है। किंतु हां, उसने कुछ अन्य दूरगामी सुधारों को स्वीकार किया था, जैसे चुनाव का व्यय भार सरकार वहन करे। यह निश्चय हुआ था कि इस संबंध में कानून बनाने से पहले सरकार विरोधी दलों से परामर्श करेगी। मेरी मांग है कि विशेषज्ञ समिति के गठन में अब और देर न की जाए तथा जनता पार्टी सरकार के शासन में स्वीकृत सुझावों को अमल में लाया जाए।

धन-बल के प्रभाव को रोकने की आवश्यकता

चुनाव में पूंजी का बढ़ता हुआ प्रभाव सदैव ही चिंता का विषय रहा है, किंतु अब तो समस्या ने बड़ा खतरनाक रूप ले लिया है। स्वदेशी धन के साथ विदेशी धन के उपयोग के समाचार भी मिले हैं। चुनाव में धन शक्ति के घातक प्रभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए—

1. चुनाव का सारा व्यय भार राज्य को

वहन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर अनुदान दिए जाएं। जो उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में सफल हों, उन्हें कानून द्वारा निर्धारित खर्च की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाए।

2. उम्मीदवार के चुनाव व्यय में उसकी पार्टी द्वारा किए गए खर्च को भी जोड़ा जाए।
3. राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित की जाए।
4. समाचार-पत्रों में विज्ञापनों, पोस्टरों, पर्ची आदि की अधिकतम व्यवस्था की जाए।
5. राजनीतिक दलों के आय-व्यय पत्रकों के ऑडिट की कानूनी व्यवस्था की जाए।
6. तारकुंडे समिति ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने तथा मताधिकार की न्यूनतम उम्र की सीमा घटाकर 18 वर्ष करने के महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन्हें स्वीकार किया जाए।

जनता सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए रेडियो तथा टेलीविजन का उपयोग करने की सुविधा देकर एक ऐतिहासिक कार्य किया था। इस सुविधा का विस्तार होना चाहिए। चुनाव प्रसारण के अतिरिक्त राजनीतिक प्रसारणों की एक योजना बननी चाहिए।

अनिवार्य मताधिकार का प्रयोग

मताधिकार के उपयोग को अनिवार्य करना भी जरूरी है। देश में अब तक 7 आम चुनाव हो चुके हैं। किंतु ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी है, जो चुनाव के प्रति सर्वथा उदासीन हैं और जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। 1977 की तरह 1980 का चुनाव भी अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ा गया था, फिर भी 35 करोड़ 40 लाख 28 हजार मतदाताओं में से केवल 20 करोड़ 12 लाख 69 हजार ने मताधिकार का उपयोग किया। इसका अर्थ यह है कि 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डालने की आवश्यकता ही नहीं समझी अनेक लोकतंत्रवादी देशों में मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य है।

विदेश नीति

वर्तमान सरकार ने नीति को दलगत राजनीति का खिलौना बनाकर इस मामले में गत तीन दशकों में विकसित राष्ट्रीय सहमति को गहरी क्षति पहुंचाई है। 1977 में जनता पार्टी ने चुनाव का मुख्य मुद्दा घरेलू मामलों को बनाया था। चुनाव जीतने के बाद विदेशी नीति की निरंतरता पर बल दिया था। 1980 और में कांग्रेस (आई) ने विदेश नीति को न केवल चुनाव के अखाड़े में घसीटा, बल्कि उसे अपने चुनाव अभियान का एक प्रमुख मुद्दा भी बनाया। यदि आज पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंधों में कुछ ठिठुरन दिखाई देती है तो उसका आरंभ चुनाव के दौरान दिए गए इन भाषणों में खोजा जाना चाहिए कि 'हमारे छोटे-छोटे पड़ोसी देश हमें आंखें दिखा रहे हैं।'

पड़ोसी देशों से बिगड़े संबंध

30 वर्षों में पहली बार अच्छे पड़ोसीपन तथा लाभदायक द्विपक्षवाद की नीति का अवलंबन कर जनता सरकार ने इस क्षेत्र में विश्वास का वातावरण बनाने में सफलता पाई थी। पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करने के पुराने तौर-तरीकों को वापस लाकर इस वातावरण को 12 मास के भीतर ही बिगाड़ दिया गया।

यह आरोप सर्वथा निराधार तथा विद्वेषपूर्ण है कि जनता सरकार ने पड़ोसी देशों की वाहवाही लूटने के लिए राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण हितों की बलि चढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ सलाल का समझौता उन्हीं शर्तों पर किया, जिनपर पुरानी सरकार समझौता करना चाहती थी, किंतु करने में विफल रही थी।

जहां तक गंगाजल के बंटवारे का सवाल है, 1975 में सरकार ने बांग्लादेश के साथ जो समझौता किया था, उसमें हमारे देश को केवल 11 हजार से 16 हजार क्यूसेक तक पानी मिला था। जनता सरकार पानी की मात्रा को बढ़ाकर 20 हजार 500 क्यूसेक तक ले जाने में सफल हुई।

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप: ढुलमुल नीति

अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक हस्तक्षेप, जो अब लगभग कब्जे का रूप धारण कर चुका है, के प्रश्न पर भारत सरकार की ढुलमुल नीति ने विश्व में देश की छवि को धूमिल किया है। इसे पड़ोसी देशों, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों और इसलामी मुल्कों से अलग-थलग कर दिया है। सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी आवाज असंदिग्ध रूप से उठाने में असफल रहने के लिए हमारे परंपरागत मित्र तथा स्वतंत्रताप्रिय अफगान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे।

हाल में ही सोवियत राष्ट्रपति श्री ब्रेझनेव के भारत आगमन के अवसर पर जारी की गई संयुक्त घोषणा में अफगानिस्तान के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया। इस बारे में भारत का मौन उसकी दोमुंही आवाज से भी अधिक मुखर है।

संदिग्ध कंपूचिया नीति

कंपूचिया में वियतनामी सेना के बल पर टिकी सरकार को मान्यता देने का भारत सरकार का फैसला भी किसी सिद्धांत से विहीन और भारत की विदेशी नीति की स्वतंत्रता के बारे में दुनिया में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, संदेह जगानेवाला है।

यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जनता सरकार ने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को प्रामाणिकता से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए भी वियतनाम पर चीन के हमले की निंदा करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं की थी। आक्रमण, आक्रमण है; वह चाहे कंपूचिया पर हो या वियतनाम पर भारत आक्रमण को नापने के दो पैमाने नहीं अपना सकता। ■

क्रमशः

अंबाला लोकसभा सदस्य रतन लाल कटारिया नहीं रहे

पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता और अंबाला से लोकसभा सदस्य श्री रतन लाल कटारिया नहीं रहे। 18 मई को उनका निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। तीन बार के सांसद श्री कटारिया पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कटारिया के निधन पर दुःख व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने जनसेवा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट किया, "सांसद और पूर्व मंत्री श्री रतन लाल कटारिया जी के निधन से दुःख पहुंचा। उन्हें सार्वजनिक सेवा और सामाजिक न्याय को लेकर उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके निधन पर ट्वीट कर कहा, "हरियाणा के अंबाला से लोकसभा सांसद

व पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। कटारिया जी आजीवन जनसेवा, सामाजिक न्याय व संगठन के लिए समर्पित रहे। उनके रुप में हमने एक सच्चा जनसेवक खोया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे।"

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री रतनलाल कटारिया के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनता की एक समर्पित कार्यकर्ता के भाव से सेवा की। हरियाणा में भाजपा को मज़बूत बनाने में उनकी सराहनीय भूमिका रही। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

अन्य कई नेताओं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी श्री कटारिया के निधन पर शोक व्यक्त किया।

श्री खट्टर ने एक ट्वीट में कहा, "पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं अंबाला से सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुःखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा संसद में आवाज उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें।" ■

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव (सीए मालदीव) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी।

आईसीएआई और सीए मालदीव का उद्देश्य लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास और संबंधित सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग स्थापित करना तथा मालदीव और भारत में लेखा व्यवसाय के विकास में सकारात्मक योगदान देना है।

यह एमओयू सीए मालदीव की मदद करने के अलावा आईसीएआई सदस्यों को लघु से दीर्घावधि भविष्य में मालदीव में पेशेवर अवसर प्राप्त करने की संभावनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस एमओयू के साथ आईसीएआई; लेखांकन पेशे में सेवाओं का निर्यात करके मालदीव के साथ साझेदारी को मजबूत करने में सक्षम होगा, आईसीएआई के सदस्य विभिन्न देशों के विभिन्न संगठनों में माध्यम से शीर्ष स्तर के पदों पर हैं और उस देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

समझौता ज्ञापन आईसीएआई के सदस्यों को अपने पेशेवर क्षितिज का विस्तार करने और स्थानीय नागरिकों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने में आईसीएआई को प्रोत्साहन प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन भारत और मालदीव के बीच मजबूत कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देगा। समझौते से दोनों देशों के पेशेवरों के आवागमन में वृद्धि होगी और साथ ही, विश्व स्तर पर व्यापार के लिए एक नए आयाम की शुरुआत होगी। ■

गुजरात की 'डबल इंजन' सरकार दोगुनी गति से काम कर रही है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को गुजरात के गांधीनगर में लगभग 4400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें शहरी विकास विभाग, जल आपूर्ति विभाग, सड़क व परिवहन विभाग और खान व खनिज विभाग से संबंधित 2,450 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 1950 करोड़ रुपये की पीएम-आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

साथ ही, इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपकर योजना के तहत निर्मित लगभग 19,000 घरों के गृह प्रवेश में हिस्सा लिया। वहीं, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए लाभार्थियों से बातचीत भी की।

इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और लाभार्थियों को बधाई दी। श्री मोदी ने बताया कि उनके लिए राष्ट्र निर्माण निरंतर चलने वाला एक 'महायज्ञ' है। उन्होंने हालिया चुनाव के बाद सत्तारूढ़ सरकार के अधीन गुजरात में विकास की गति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। श्री मोदी ने हाल ही में 3 लाख करोड़ रुपए के गरीब समर्थक गुजरात के बजट का उल्लेख किया। उन्होंने 'वंचितों को प्राथमिकता देने' की भावना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की सराहना की।

श्री मोदी ने राज्य में 25 लाख आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 2 लाख माताओं को सहायता, 4 नए मेडिकल कॉलेज और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए हजारों करोड़ रुपये के कार्यों जैसी कुछ हालिया पहलों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पता चलता है कि गुजरात की डबल इंजन सरकार दोगुनी गति से काम कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में लोगों ने अभूतपूर्व विकास को देखा है। उन्होंने उस समय को याद किया जब नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी दुर्लभ थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उस निराशा से बाहर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति तक योजनाओं का सौ फीसदी लाभ पहुंचाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय तब होता है, जब सरकार समाज में सभी के लाभ के लिए काम करती है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 32,000 घरों का निर्माण पूरा करने के साथ लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि गरीबों के आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी होती है, जब वे जीवन की बुनियादी जरूरतों के बारे में कम से कम चिंतित होते हैं। ■

'भारत सरकार राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र में विश्वास करती है'

राजस्थान के नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मई को राजस्थान के नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। सभा के संबोधन में प्रधानमंत्री ने भगवान श्रीनाथ की गौरवशाली भूमि, मेवाड़ के दर्शन का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम से पहले नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन और पूजा करने को याद किया। उन्होंने आजादी के अमृत काल में एक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद की कामना की।

प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा

जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ तथा जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया, उनका उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं राजस्थान की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के उदयपुर से शामलाजी खंड को छह लेन करने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को फायदा होगा, वहीं एनएच-25 के बिलाड़ा-जोधपुर खंड से जोधपुर से सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि श्री नाथद्वारा से नई रेलवे लाइन मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ेगी, जिससे संगमरमर, ग्रेनाइट और खनन उद्योग जैसे क्षेत्रों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र में विश्वास करती है।

श्री मोदी ने राजस्थान में पर्यटन और आस्था के स्थलों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ने के लाभों को भी रेखांकित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य, भामाशाह की उदारता और वीर पन्नाधाय के त्याग की गाथाओं को याद किया। ■

भाजपा ने आंध्र प्रदेश में 'प्रजा पोरु यात्रा' का आयोजन किया

सुनील देवधर

आंध्र प्रदेश भ्रष्ट वाईएसआरसीपी सरकार से पीड़ित है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सभी मोर्चों पर विफल हो रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में भाजपा एक संगठन के तौर पर आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच संगठन के आधार को बढ़ाने के लिए हाल ही में भाजपा आंध्र प्रदेश प्रदेश इकाई द्वारा आरंभ एक पहल काफी हद तक सफल रही है। इस लेख के माध्यम से मैं उक्त पहल के बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूं। जब भाजपा के राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) श्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्री वी. मुरलीधरन, प्रदेश अध्यक्ष श्री सोमू वीरराजू, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री मधुकर और अन्य प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन के बारे में चर्चा की, तो एक अनूठी पहल सामने आई और इसे 'प्रजा पोरु स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स' की उपाधि दी गई। इस तेलुगु शब्द 'प्रजा पोरु' का अर्थ 'जनता की लड़ाई' है।

आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 45,000 मतदान केंद्र हैं और प्रत्येक शक्ति केंद्र के दायरे में 4 या 5 मतदान केंद्र लाकर पूरे राज्य में कुल 10,000 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। इन 10,000 शक्ति केंद्रों में से लगभग 8,000 शक्ति केंद्रों में कम से कम एक कार्यकर्ता मौजूद है और उसे शक्ति केंद्र प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रदेश की एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए हमने शक्ति केंद्र पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई और एक लक्ष्य निर्धारित किया कि एक महीने की अवधि में 5,000 नुक्कड़ सभाएं की जाएं।

इन सभी नुक्कड़ सभाओं में हमने देश की अखंडता को मजबूत करने के साथ-साथ भारत की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, गरीब और वंचित लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए जा रहे पथ प्रदर्शक कार्यों के बारे में जानकारी फैलाने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, हमने आंध्र प्रदेश के लोगों को जगन मोहन रेड्डी के विफल शासन से अवगत कराने का भी फैसला किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चार अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया। इन नुक्कड़ सभाओं के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। एक समिति जिसे मसौदा समिति कहा जाता है, गठित की गई। उक्त समिति का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की जन-समर्थक योजनाओं को सूचीबद्ध करने वाले एक दस्तावेज का मसौदा तैयार करना और मुख्यमंत्री जगन की विफलताओं को सूचीबद्ध करने वाला एक अन्य दस्तावेज तैयार करना था। कुछ जगहों पर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्थानीय मुद्दों को सूचीबद्ध करने वाले दस्तावेज भी तैयार किए गए।

> हमने देश की अखंडता को मजबूत करने के साथ-साथ भारत की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, गरीब और वंचित लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए जा रहे पथप्रदर्शक कार्यों के बारे में जानकारी फैलाने का निर्णय लिया

प्रचार-प्रसार और अन्य सामग्री की देखभाल के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में साहित्य, पार्टी के झंडे, टोपियां, पोस्टर, बैनर, स्टिकर आदि की आपूर्ति का पर्याप्त ध्यान रखा गया। 'प्रजा पोरु यात्रा' के आयोजन में सबसे बड़ा मुद्दा वक्ताओं का था। जैसाकि एक महीने के अंतराल में 5,000 बैठकें करने की योजना थी, तो कम से कम 166 बैठकें प्रतिदिन करना आवश्यक था। ऐसे में सभाओं को संबोधित करने के लिए कई वक्ताओं की आवश्यकता हुई।

इसको देखते हुए प्रदेश इकाई ने एक वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया और उसी में विषय प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की गई। जैसे-जैसे कार्यक्रम आरंभी हुआ, वैसे-वैसे लोगों की दिलचस्पी दिन-ब-दिन बढ़ती गई और प्रजा पोरु सभाएं सफल होती गईं और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता गया। जबकि हमने 5,000 बैठकों की कल्पना की है, यह आंकड़ा वास्तव में उक्त एक महीने के अंत में 6,700 से अधिक बैठकों तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा।

प्रजा पोरु बैठकों के कुछ लाभ

1. भाजपा एक संगठन के रूप में प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय हुआ और आंध्र प्रदेश के लोगों में उत्साह का माहौल बना।
2. इस पहल के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर बूथ कमेटियां बनाई गईं, जहां पहले पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था।
3. बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और सदस्य, जो अपने-अपने दलों से नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इसके साथ ही सूक्ष्म स्तर पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम पूरे किए गए।

4. आंध्र प्रदेश में मीडिया का एक वर्ग हमारा विरोधी है। लगभग सभी मीडिया हाउस हमारे बारे में झूठ फैलाने का काम करते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत कम गतिविधियां होती हैं। लेकिन प्रजा पोरु सभाओं की सफलता के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के विचार, मोदी सरकार के महान कार्य प्रदेश की जनता तक पहुंचे। यहां तक कि मुख्यधारा के टीवी चैनलों और समाचार पत्रों को भाजपा के इस 'सफल अभियान' का संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
5. इस अभियान कारण जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्माण सहयोग मिला, समाज के सभी वर्गों के लोग पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर जुड़े,और हम इस बात को मजबूती के साथ जनता तक ले जाने में सफल रहे कि भाजपा भ्रष्ट जगन मोहन रेड्डी सरकार का एक विकल्प है।

हमारे इस कार्यक्रम से वाईएसआरसीपी के कई विधायक और नेता चिंतित थे और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को रोकने को पूरा प्रयास किया।

बहरहाल, मैं उन कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत की; मुद्दों पर अपना समय, ऊर्जा और प्रयास लगाये और हमारे कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और भाजपा, आंध्र प्रदेश के सह–प्रभारी हैं)

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II के अंतर्गत 50 प्रतिशत गांव अब खुले में शौच मुक्त

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 10 मई को जारी एक बयान के अनुसार अब देश के कुल गांवों में से आधे गांवों (50 प्रतिशत) ने मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ने खुले में शौच मुक्त (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) का दर्जा हासिल कर लिया है। खुले में शौच मुक्त गांव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जहां ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है। अब तक 2.96 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। यह 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण-II लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खुले में शौच मुक्त 2,96,928 गांवों में से 2,08,613 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के साथ खुले में शौच मुक्त आकांक्षी गांव हैं। 32,030 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था साथ खुले में शौच मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए गांव हैं और 56,285 गांव खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव हैं। खुले में शौच

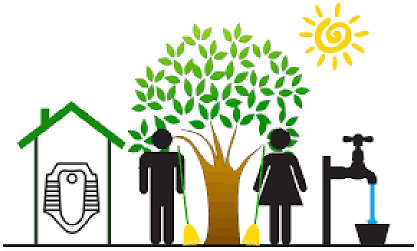

मुक्त मॉडल गांव वह है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए हुए है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।

इन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का निरीक्षण किया जाता है, अर्थात न्यूनतम कूड़ा-कचरा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं, खुले में शौच मुक्त क्षेत्र की सूचना का प्रदर्शन और शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेशों को भी प्रदर्शित किया जाता है। अभी तक 1,65,048 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, 2,39,063 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, 4,57,060 गांवों में न्यूनतम जमा पानी है जबकि 4,67,384 गांवों में न्यूनतम कचरा है।

वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कुल 83,938 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2023-24 52,137 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) निधियों के अतिरिक्त स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग की निधियों ने स्पष्ट रूप से अगल आवंटन किया है। इन निधियों का उपयोग स्वच्छता संपत्तियों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए किया गया है।

इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो गए हैं। खुले में शौच मुक्त गांवों ने 50 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है यह स्वच्छता के क्षेत्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सिर्फ शौचालयों के निर्माण और उपयोग से आगे बढ़कर पूर्ण और पूर्ण स्वच्छता यानी खुले में शौच मुक्त से खुले में शौच मुक्त प्लस तक जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और रहन-सहन को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आई कई रिपोर्टों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के प्रभाव की प्रशंसा की गई है। ■

'पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12 मई, 2023 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'डेमोक्रेसी इन कोमा - साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल' का विमोचन किया और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अनाचार और अत्याचार पर विस्तार से चर्चा करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने पुस्तक की लेखिकाओं सोनाली चितलकर, विजिता एस. अग्रवाल, श्रुति मिश्रा और मोनिका अग्रवाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार में महिलाओं की वर्तमान भयावह स्थिति को पूरे देश के सामने रखने का महती कार्य किया है। इस कार्यक्रम में एनएचआरसी के पूर्व चेयरमैन एवं जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जज श्री एम.एम. कुमार, पश्चिम बंगाल के भाजपा सह-प्रभारी एवं भाजपा, आईटी विभाग के अध्यक्ष श्री अमित मालवीय, ऑर्गनाइजर वीकली के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर और भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड के एमडी श्री भारत भूषण अरोड़ा भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को लेकर 'डेमोक्रेसी इन कोमा - साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल' पुस्तक लिखी गई है। इसे पढ़कर मैं काफी विचलित हुआ। हमारी धरती लोकतंत्र की जननी कही जाती है। देश में कहा जाता था कि भारत जो कल सोचता है, वह बंगाल आज सोचता है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कई रूप में बंगाल देश में अग्रणी रहा है। साहित्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में बंगाल की विभूतियों ने देश को दिशा दिखाई है। देश को कई सामाजिक और राजनीतिक सुधारक पश्चिम बंगाल की भूमि से मिले हैं। लेकिन, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के शासन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देख कर बहुत ही दुःख होता है। श्री नड्डा ने कहा कि मैं एक ही बात कहूंगा कि सच में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। यह कहना सही है कि डेमोक्रेसी इज इन कोमा इन वेस्ट बंगाल। हमे लोगों को जागृत करना होगा और पश्चिम बंगाल के गौरव को पुनः स्थापित करना होगा। ■

पीपीआरसी ने 'मन की बात से जन की बात' रिपोर्ट भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी

लोक नीति शोध केन्द्र (पीपीआरसी) के निदेशक डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, डॉ. सुमीत भसीन और उनकी टीम ने 01 मई, 2023 को नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर उनको 'मन की बात से जन की बात' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट सौंपी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात की सराहना की कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से अपने भावपूर्ण संवाद और प्रेरणा से देश और समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे 'मन की बात' भारत के लोगों की सामूहिक भावनाओं का जश्न मनाने का एक माध्यम बन गया है और यह कार्यक्रम उनकी प्रेरक जीवन यात्रा पर प्रकाश डाल रहा है।

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कैसे प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भारतीय विरासत और संस्कृति, ऊर्जा, लैंगिक न्याय और शासन जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के साथ-साथ स्थिरता के महत्व पर जोर दिया है।

डॉ. सुमीत भसीन ने 'मन की बात' के बारे में कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें भारतीयों को उनकी समृद्ध विरासत के साथ फिर से जोड़ने, देश के कोने-कोने से प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करने, कोविड-19 महामारी के दौरान सकारात्मकता का माहौल पैदा करने और लोगों की जीवन शैली आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्यावरण से लेकर जन भागीदारी के लिए समाज को जागृत करने में मन की बात कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला।

पीपीआरसी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के रेडियो प्रसारण कार्यक्रम द्वारा राष्ट्र में लाए गए परिवर्तन के तीन प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालती है और इस बात को बताती है कि यह देश के त्वरित विकास के लिए विशेष रूप से 'अमृत काल' के दौरान कैसे एक योगदान कारक बन गया है। ये तीन पहलू हैं:

- भारत की 'जन शक्ति' को जागृत करना
- देश की मानसिकता में सुधार और एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना
- 'भारतीय' जीवन-शैली को बढ़ावा देना ■

प्रधानमंत्री ने ओडिशा में अनेक रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा में 8000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं। परियोजनाओं में पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाना, पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखना, ओडिशा में शत-प्रतिशत विद्युतीकृत रेल नेटवर्क समर्पित करना, संबलपुर-टिटलागढ़ रेल लाइन का दोहरीकरण, अंगुल-सुकिंदा के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन; मनोहरपुर-राउरकेला-झारसुगुड़ा-जमगा को जोड़ने वाली तीसरी लाइन और बिछुपाली-झरतरभा के बीच एक नई ब्रॉड-गेज लाइन बिछाना शामिल है।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को आज वंदे भारत एक्सप्रेस भेंट की जा रही है जो आधुनिक और आकांक्षी भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत की गति और प्रगति तब देखी जा सकती है, जब वंदे भारत ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। श्री मोदी ने कहा कि यह गति अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में देखी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों के यात्रा के अनुभव के साथ-साथ विकास के मायने भी पूरी तरह बदल जाएंगे। अब दर्शन के लिए कोलकाता से पुरी की यात्रा हो या पुरी से कोलकाता आना हो, प्रधानमंत्री ने बताया कि यात्रा का समय अब घटकर केवल साढ़े छह घंटे रह जाएगा, जिससे समय की बचत होगी, इससे व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति का लाभ उन राज्यों को मिल रहा है, जो विकास में पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा में रेल योजनाओं के लिए बजट में काफी वृद्धि की गई है। श्री मोदी ने बताया कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में राज्य में हर साल केवल 20 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाती थी, जबकि वर्ष 2022-23 में केवल एक वर्ष में 120 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई गईं।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित खुर्दा बोलनगीर लाइन और हरिदासपुर-पारादीप लाइन जैसी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में शत-प्रतिशत विद्युतीकृत रेल नेटवर्क को देश को समर्पित किया। इससे प्रचालन और रखरखाव लागत में कमी आएगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। श्री मोदी ने संबलपुर-टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण, अंगुल-सुकिंदा के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, मनोहरपुर-राउरकेला-झारसुगुडा-जम्गा को कनेक्ट करने वाली तीसरी लाइन और बिछुपाली-झारतरभा के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन को भी समर्पित किया। ये ओडिशा में इस्पात, बिजली एवं खनन क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई यातायात मांगों को पूरी करेंगे तथा इन रेल खंडों में यात्री यातायात पर दबाव कम करने में भी सहायता करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता

संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं की अनुमोदन रेटिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी को 78 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई और वह इस सूची में शीर्ष पर हैं। इस सर्वेक्षण में 22 देशों के नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें से केवल तीन अन्य नेताओं की अनुमोदन रेटिंग 50 प्रतिशत से अधिक है।

सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी को 78 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति सर्वश्री एलेन बेर्सेट को 62 प्रतिशत, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर को 62 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस को 53 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। देखा जाए तो सिर्फ 4 नेताओं को 50 प्रतिशत से ज्यादा रेटिंग मिली है।

'आप बहुत लोकप्रिय हैं': जो बाइडेन

इस रेटिंग के प्रकाशित होने से कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को 'बहुत लोकप्रिय' नेता के रूप में संबोधित किया था। श्री बाइडेन ने कहा, "आप दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आप मेरे लिए एक वास्तविक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम आपके लिए वाशिंगटन में डिनर आयोजित कर रहे है। पूरे देश से हर कोई वहां आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। मेरी टीम से पूछ लें। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी। आप बहुत लोकप्रिय हैं, और 'मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए।' ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)...................................... (2)......................................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :...................................... दिनांक :...................................... बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

हिरोशिमा (जापान) में 19 मई, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा और प्रवासी भारतीय समुदाय

हिरोशिमा (जापान) में 20 मई, 2023 को क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हिरोशिमा (जापान) में 20 मई, 2023 को जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान सामूहिक तस्वीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्यजन

पोर्ट मोरेस्बी (पापुआ न्यू गिनी) में 21 मई, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे

पोर्ट मोरेस्बी (पापुआ न्यू गिनी) में 22 मई, 2023 को तीसरे एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन के दौरान सामूहिक तस्वीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 30 मई, 2023
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

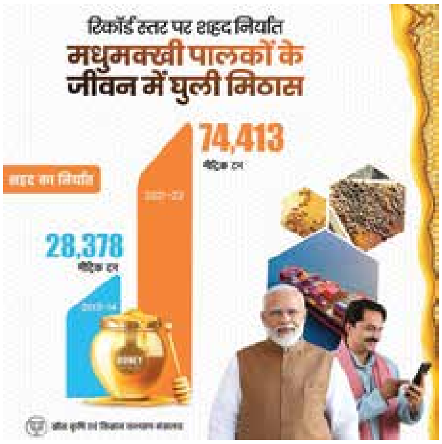

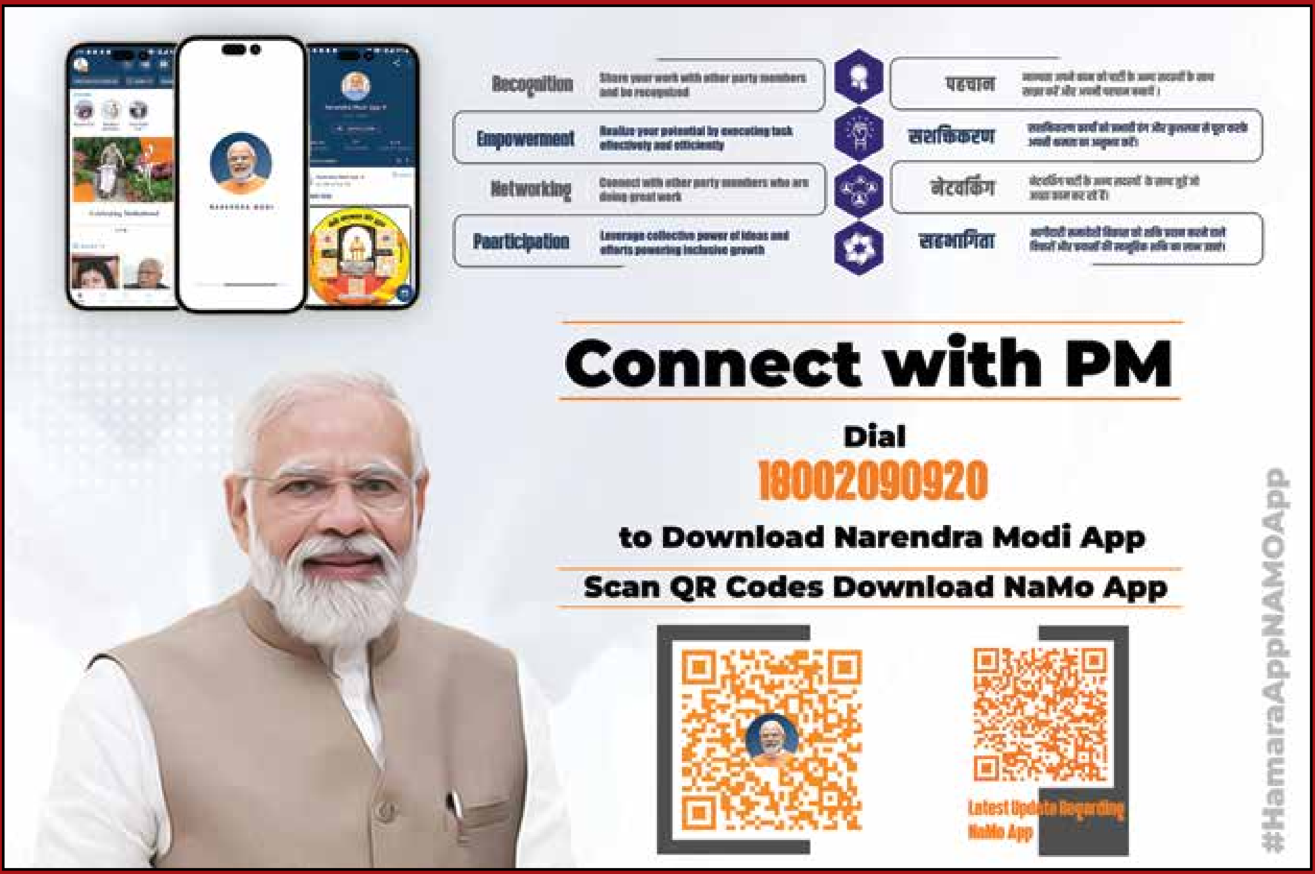

छायाकार: अजय कुमार सिंह